

**KEDIA**  
**सेजस्थान**  
अजमेर रोड, जयपुर

www.rera.rajasthan.gov.in  
RERA No. RAJ/P/2023/2387



# मलाल करोगे ?

या

# मालामाल बनोगे ?



**5 दिन में 5 लाख रेट बढ़ेगी !**



₹ 4000/- में फ्लैट				₹ 5200/- में कोठी						
PRODUCT TYPE	UNIT TYPE	SIZE	PRESENT RATE	30 JUNE 2026	31 JULY 2026	31 AUG. 2026	30 SEPT. 2026	31 OCT. 2026	30 NOV. 2026	30 DEC. 2026
WALK-UP APARTMENT	2 BHK (GF)	1350 Sq Ft	66 Lacs	68 Lacs	70 Lacs	72 Lacs	74 Lacs	76 Lacs	78 Lacs	80 Lacs
	3 BHK (SF)	1900 Sq Ft	76 Lacs	78 Lacs	80 Lacs	82 Lacs	84 Lacs	86 Lacs	88 Lacs	90 Lacs
	3 BHK (FF)	1900 Sq Ft	82.5 Lacs	85 Lacs	87.5 Lacs	90 Lacs	92.5 Lacs	95 Lacs	97.5 Lacs	1 Cr
KOTHI	3 BHK BIG	2000 Sq Ft	1.075 Cr	1.10 Cr	1.125 Cr	1.15 Cr	1.175 Cr	1.20 Cr	1.225 Cr	1.25 Cr
	4 BHK BIGGER	2325 Sq Ft	1.29 Cr	1.32 Cr	1.35 Cr	1.38 Cr	1.41 Cr	1.44 Cr	1.47 Cr	1.50 Cr
	4 BHK BIGGEST	3200 Sq Ft	1.65 Cr	1.70 Cr	1.75 Cr	1.80 Cr	1.85 Cr	1.90 Cr	1.95 Cr	2 Cr

**KEDIA**

1800-120-2323  
78770-72737

info@kedia.com  
www.kedia.com



**आन्दोलन**  
अशुद्ध के विरुद्ध

**KEDIA**  
**Pavitra**



## भारत का असली Social Media



सब बढ़िया... तू सुना



चाय प्रेमियों के लिए खास ब्लेन्ड

STRONG GOLDEN LIQUOR

SILIGURI'S FINEST TEA BLEND

RICH & BOLD AROMA

केडिया पवित्र टीम को अपनी दुकान में बुलाने के लिये  
या अपनी नजदीकी दुकान तक केडिया पवित्र उपलब्ध करवाने के लिए  
अपनी गूगल लोकेशन 90704-90704 पर WhatsApp करें या 1800-120-2727 पर कॉल करें।  
हमारी टीम 24 घंटे के भीतर प्रोडक्ट्स की डिलीवरी एवं उपलब्धता सुनिश्चित करेगी।

अगर आप किसी भी FMCG कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ सेल्समैन हैं  
तो डायरेक्ट केडिया पवित्र में जाँव हेतु आवेदन करें:  
Email ID : bdm@kediapavitra.com | Call : +91 90704-90704



# बेटा 27 का, बेरोजगार... लड़की वाले मना कर गए!

कक्षा 10 के बाद कलम के साथ कारीगरी, तभी बसेगा घर



मदन सिंह काला

55 लाख सरकारी कुर्सियाँ खाली हैं। 65 करोड़ युवा भटक रहे हैं क्योंकि उनके पास स्किल नहीं है। 27 साल का बेटा। घर में तनाव। लड़की वाले आए, चाय-नास्ता करते हुए पूछ लिया 'बेटा करते क्या हो?'। जबकि पिता- 'सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ सर।' बस रिश्ता यहीं खटाई में पड़ गया। ये कहानी हर गली-मोहल्ले की हो

3 लाख साल पहले अफ्रीका महाद्वीप की इथियोपिया-मोरक्को के भूभाग पर आधुनिक मानव-होमो सेपियंस-के रूप में विकसित हुआ। 2017 में नेचर जर्नल में प्रकाशित शोध के अनुसार मोरक्को के जेबेल इरहूद में मिली 3 लाख साल पुरानी खोपड़ी इसका प्रमाण है। उसका माथा ऊँचा था, टुड्डु उभरी हुई थी, दिमाग 1350 ग्राम का था। 65 हजार साल पहले उसका एक समूह अरब सागर के किनारे-किनारे चलकर भारतीय उपमहाद्वीप पहुँचा। गुजरात के तट से उत्तरकर वह पूरे भारत में फैल गया। आज भी 50 से 65 प्रतिशत भारतीयों का डीएनए एक है। मतलब हम सबके पूर्वज एक ही हैं। फिर जाति-धर्म की दीवार क्यों? ये दीवार 200 साल की मजबूरी थी। 1000 साल का विश्वास नहीं। आज हाथ में स्कूल बगैरे तो जाति पूछने वाला शर्मोष्ण। क्योंकि पेट जाति निकलता है, पेट रोटी देखाता है। और रोटी स्किल से बनती है, जाति से नहीं।

यदि युवाओं को कक्षा 10 के बाद पढ़ाई के साथ रोजगार मिल जाए तो संविधान की प्रस्तावना के तिनो न्याय में से आर्थिक न्याय मिलना शुरू हो जाएगा। हमारी संविधान प्रस्तावना कहती है- हम भारत के लोग, भारत की सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतान्त्रिक गणराज्य बनाने के लिए और उसके सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय दिलाने के लिए संकल्पित हैं। अनुच्छेद 41 कलम है राज्य काम पाने का अधिकार सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। जब 18 साल का युवा कक्षा 10 के बाद 20 हजार रुपये कमाने लगेगा तो वह आर्थिक न्याय की पहली सीढ़ी चढ़ जाएगा। बिना रोजगार के प्रस्तावना का 'आर्थिक न्याय' कागज पर ही रह जाएगा।

55 लाख खाली कुर्सियों का लेखा-जोखा केन्द्र-राज्य-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम-पंचायत में 1.8 करोड़ पद स्वीकृत हैं, पर 55 लाख कुर्सियाँ आज भी खाली पड़ी हैं। फिर भी सरकारी खजाने से 3.5 करोड़ लोग बेरोजगार उठा रहे हैं- इसमें सेवारत 1.25 करोड़ कर्मचारी, 1 करोड़ पेशेवर और 1.25 करोड़ ठेका-संवित्ता-ऑनलाइन-आशा कार्यक्रमों जैसे अर्द्धसरकारी लोग शामिल हैं। यानी कुर्सी 1.8 करोड़ की है, पर बोझ 3.5 करोड़ का। 50 प्रतिशत नहीं भती अब ठेके-अनुबन्ध पर हो रही है,

फिर औद्योगिक क्रांति आई। इंग्लैंड की कपड़ा मिल हो या जपान की सिल्क फैक्ट्री, जब कलम-लड़की 8 घण्टे एक मशीन पर खुद हुए तो तीन बदलाव हुए। स्त्री के हाथ में तनख्वाह आई तो वह बोझ से सहारा बन गई। उसे 'फ्लॉ की बेटों' की जगह 'एना - मशीन ऑपरेटर' कहा जाने लगा। रोज 8 घण्टे साथ काम होगा तो लड़का-लड़की एक-दूसरे का गुस्सा, ईमानदारी, मेहनत देख लेंगे। कुण्डली की जरूरत नहीं पड़ेगी। जर्मनी में आज 40 प्रतिशत शायियाँ ऑफिस-फैक्ट्री में होती हैं। वहीं कोई नहीं पूछता तुम कौन सी जाति हो, पूछते हैं 'तुम प्रोजेक्ट हैंडल कैसे करते हो?' यानी काम की जिम्मेदारी कैसे निभाती हो। मतलब साफ है- जब स्त्री-पुरुष साथ काम करेंगे तो जीवनसाथी का चुनाव कुण्डली से नहीं, आचरण से होगा। जाति और दहेज दोनों अपने आप खत्म हो जाएँगे।

जर्मनी में कक्षा 10 के बाद 70 प्रतिशत बच्चे 'ड्युअल सिस्टम' में चले जाते हैं। सप्ताह में तीन दिन कम्पनी में मशीन चलाने हैं, दो दिन स्कूल जाते हैं। महीने के अन्त में एक लाख रुपये स्ट्राइपेण्ड लेते हैं। 18 साल का लड़का अपने पैरों पर खड़ा होता है, पीजी यानी किराये का कमरा लेता है, बाइक लेता है। बेरोजगारी 3 प्रतिशत है। स्विट्जरलैंड में 60 प्रतिशत युवा 16 साल के बाद बैंक और फैक्ट्री में व्यावसायिक शिक्षा करते हैं। स्ट्राइपेण्ड सवा लाख रुपये महीना मिलता है। लड़की 20 साल की उम्र में बैंक में 90 हजार कमाती है इसलिए शादी समनता की होती है, समझौते की नहीं। जापान ने 15 साल के बच्चों को टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम सिखाया। इन 25 से ज्यादा देशों का एक मन्त्र है- कक्षा 10 के बाद भटकना नहीं, स्किला जर्मनी का 18 साल का लड़का 1 लाख महीना कमाता है। भारत का 27 साल का लड़का 'तैयारी कर रहा हूँ' बोलता है। शर्म किसे आनी चाहिए? एनसीआईबी का डेटा कहता है। 18 से 25 साल के युवाओं की कुल अपराध में भागीदारी 45 प्रतिशत है। क्यों? क्योंकि जर्मनी का युवा 16 से काम कर रहा है, भारत का युवा 18 से 25 तक 'तैयारी कर रहा हूँ' बोलकर खाली बैठता है। खाली दिमाग में शैतानियत का उदय होता है। भारत की घरती में 41.7 अरब टन हाइड्रोकार्बन, 1.23 करोड़ टन लिथियम है, पर तेल का सिर्फ 6-8 प्रतिशत निकल रहा है। हम कच्चा लोहा 40 रुपये किलो बेचकर चीन से स्टील 100 रुपये किलो खरीदते हैं। फर्क सिर्फ गलाने वाले हाथ का है। फैक्ट्रियों हैं पर 40 प्रतिशत पर खाली हैं क्योंकि 10वीं पास सीएनसी मशीन नहीं चला पाएँ। इम्पोर्टर को 10 सेल्समैन चाहिए, मैनुफैक्चर को 1000 मजदूर। हर साल 6 लाख करोड़ रुपये के हथियार बहार से मँगते हैं। एक लड़कू विमान 800 करोड़ का। अगर यही हाल हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल में बने तो 20 हजार युवा को रोजगार मिले और वही पैसा आइएसआरओ में लगे। जापान ने 1945 के बाद हथियार नहीं बनाए, स्किल बनाई और आज कार बेचता है। हम स्किल नहीं दे रहे इसलिए आज भी खरीद रहे हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बन गया है। अप्रैल 2025 से फरवरी 2026 तक 13.5 लाख करोड़ रुपये का व्यापार घाटा। मतलब हम दुनिया को कर्ज का कागज देते हैं, बदले में माल लेते हैं।

कबीर का मानव शक्ति के उपयोग के लिए आख्यान आलसी पीढ़ी और सरकार दोनों के लिए है- 'काल करे सो आज कर, आज करे सो अबा। पल में बल्य होयगी, बहुरी करोगे कबा।' यानी कल नहीं, आज नहीं-अभी। 18 साल का लड़का आईटीआई का फॉर्म कल भरेगा तो 27 साल 'तैयारी' में निकल जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 41 कहता है राज्य काम पाने का अधिकार सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। ये प्रयास अर्थ कर्तव्य बनना चाहिए। इसलिए उर्द्ध्व दे

परमाणु नहीं। ठेके पर काम करने वाले युवाओं का शोषण होता है, उन्हें परिवार चलाने का पर्याप्त पैसा नहीं मिलता, न भविष्य की सुरक्षा मिलती है। ये 55 लाख खाली पद अगर कक्षा 10 के बाद 'Dual Work System' से भरे जाएँ तो 18 साल का युवा अप्रेंटिस बनकर 20 हजार कमा लेगा। न वो बेरोजगार कहलाएगा, न सरकार पर पैशन का बोझ बढ़ेगा। कुर्सी भरेगी, युवा बसेगा, देश बसेगा।

परमाणु नहीं। ठेके पर काम करने वाले युवाओं का शोषण होता है, उन्हें परिवार चलाने का पर्याप्त पैसा नहीं मिलता, न भविष्य की सुरक्षा मिलती है। ये 55 लाख खाली पद अगर कक्षा 10 के बाद 'Dual Work System' से भरे जाएँ तो 18 साल का युवा अप्रेंटिस बनकर 20 हजार कमा लेगा। न वो बेरोजगार कहलाएगा, न सरकार पर पैशन का बोझ बढ़ेगा। कुर्सी भरेगी, युवा बसेगा, देश बसेगा।

परमाणु नहीं। ठेके पर काम करने वाले युवाओं का शोषण होता है, उन्हें परिवार चलाने का पर्याप्त पैसा नहीं मिलता, न भविष्य की सुरक्षा मिलती है। ये 55 लाख खाली पद अगर कक्षा 10 के बाद 'Dual Work System' से भरे जाएँ तो 18 साल का युवा अप्रेंटिस बनकर 20 हजार कमा लेगा। न वो बेरोजगार कहलाएगा, न सरकार पर पैशन का बोझ बढ़ेगा। कुर्सी भरेगी, युवा बसेगा, देश बसेगा।

परमाणु नहीं। ठेके पर काम करने वाले युवाओं का शोषण होता है, उन्हें परिवार चलाने का पर्याप्त पैसा नहीं मिलता, न भविष्य की सुरक्षा मिलती है। ये 55 लाख खाली पद अगर कक्षा 10 के बाद 'Dual Work System' से भरे जाएँ तो 18 साल का युवा अप्रेंटिस बनकर 20 हजार कमा लेगा। न वो बेरोजगार कहलाएगा, न सरकार पर पैशन का बोझ बढ़ेगा। कुर्सी भरेगी, युवा बसेगा, देश बसेगा।

परमाणु नहीं। ठेके पर काम करने वाले युवाओं का शोषण होता है, उन्हें परिवार चलाने का पर्याप्त पैसा नहीं मिलता, न भविष्य की सुरक्षा मिलती है। ये 55 लाख खाली पद अगर कक्षा 10 के बाद 'Dual Work System' से भरे जाएँ तो 18 साल का युवा अप्रेंटिस बनकर 20 हजार कमा लेगा। न वो बेरोजगार कहलाएगा, न सरकार पर पैशन का बोझ बढ़ेगा। कुर्सी भरेगी, युवा बसेगा, देश बसेगा।

परमाणु नहीं। ठेके पर काम करने वाले युवाओं का शोषण होता है, उन्हें परिवार चलाने का पर्याप्त पैसा नहीं मिलता, न भविष्य की सुरक्षा मिलती है। ये 55 लाख खाली पद अगर कक्षा 10 के बाद 'Dual Work System' से भरे जाएँ तो 18 साल का युवा अप्रेंटिस बनकर 20 हजार कमा लेगा। न वो बेरोजगार कहलाएगा, न सरकार पर पैशन का बोझ बढ़ेगा। कुर्सी भरेगी, युवा बसेगा, देश बसेगा।

परमाणु नहीं। ठेके पर काम करने वाले युवाओं का शोषण होता है, उन्हें परिवार चलाने का पर्याप्त पैसा नहीं मिलता, न भविष्य की सुरक्षा मिलती है। ये 55 लाख खाली पद अगर कक्षा 10 के बाद 'Dual Work System' से भरे जाएँ तो 18 साल का युवा अप्रेंटिस बनकर 20 हजार कमा लेगा। न वो बेरोजगार कहलाएगा, न सरकार पर पैशन का बोझ बढ़ेगा। कुर्सी भरेगी, युवा बसेगा, देश बसेगा।

परमाणु नहीं। ठेके पर काम करने वाले युवाओं का शोषण होता है, उन्हें परिवार चलाने का पर्याप्त पैसा नहीं मिलता, न भविष्य की सुरक्षा मिलती है। ये 55 लाख खाली पद अगर कक्षा 10 के बाद 'Dual Work System' से भरे जाएँ तो 18 साल का युवा अप्रेंटिस बनकर 20 हजार कमा लेगा। न वो बेरोजगार कहलाएगा, न सरकार पर पैशन का बोझ बढ़ेगा। कुर्सी भरेगी, युवा बसेगा, देश बसेगा।

परमाणु नहीं। ठेके पर काम करने वाले युवाओं का शोषण होता है, उन्हें परिवार चलाने का पर्याप्त पैसा नहीं मिलता, न भविष्य की सुरक्षा मिलती है। ये 55 लाख खाली पद अगर कक्षा 10 के बाद 'Dual Work System' से भरे जाएँ तो 18 साल का युवा अप्रेंटिस बनकर 20 हजार कमा लेगा। न वो बेरोजगार कहलाएगा, न सरकार पर पैशन का बोझ बढ़ेगा। कुर्सी भरेगी, युवा बसेगा, देश बसेगा।

परमाणु नहीं। ठेके पर काम करने वाले युवाओं का शोषण होता है, उन्हें परिवार चलाने का पर्याप्त पैसा नहीं मिलता, न भविष्य की सुरक्षा मिलती है। ये 55 लाख खाली पद अगर कक्षा 10 के बाद 'Dual Work System' से भरे जाएँ तो 18 साल का युवा अप्रेंटिस बनकर 20 हजार कमा लेगा। न वो बेरोजगार कहलाएगा, न सरकार पर पैशन का बोझ बढ़ेगा। कुर्सी भरेगी, युवा बसेगा, देश बसेगा।

परमाणु नहीं। ठेके पर काम करने वाले युवाओं का शोषण होता है, उन्हें परिवार चलाने का पर्याप्त पैसा नहीं मिलता, न भविष्य की सुरक्षा मिलती है। ये 55 लाख खाली पद अगर कक्षा 10 के बाद 'Dual Work System' से भरे जाएँ तो 18 साल का युवा अप्रेंटिस बनकर 20 हजार कमा लेगा। न वो बेरोजगार कहलाएगा, न सरकार पर पैशन का बोझ बढ़ेगा। कुर्सी भरेगी, युवा बसेगा, देश बसेगा।

परमाणु नहीं। ठेके पर काम करने वाले युवाओं का शोषण होता है, उन्हें परिवार चलाने का पर्याप्त पैसा नहीं मिलता, न भविष्य की सुरक्षा मिलती है। ये 55 लाख खाली पद अगर कक्षा 10 के बाद 'Dual Work System' से भरे जाएँ तो 18 साल का युवा अप्रेंटिस बनकर 20 हजार कमा लेगा। न वो बेरोजगार कहलाएगा, न सरकार पर पैशन का बोझ बढ़ेगा। कुर्सी भरेगी, युवा बसेगा, देश बसेगा।

परमाणु नहीं। ठेके पर काम करने वाले युवाओं का शोषण होता है, उन्हें परिवार चलाने का पर्याप्त पैसा नहीं मिलता, न भविष्य की सुरक्षा मिलती है। ये 55 लाख खाली पद अगर कक्षा 10 के बाद 'Dual Work System' से भरे जाएँ तो 18 साल का युवा अप्रेंटिस बनकर 20 हजार कमा लेगा। न वो बेरोजगार कहलाएगा, न सरकार पर पैशन का बोझ बढ़ेगा। कुर्सी भरेगी, युवा बसेगा, देश बसेगा।

परमाणु नहीं। ठेके पर काम करने वाले युवाओं का शोषण होता है, उन्हें परिवार चलाने का पर्याप्त पैसा नहीं मिलता, न भविष्य की सुरक्षा मिलती है। ये 55 लाख खाली पद अगर कक्षा 10 के बाद 'Dual Work System' से भरे जाएँ तो 18 साल का युवा अप्रेंटिस बनकर 20 हजार कमा लेगा। न वो बेरोजगार कहलाएगा, न सरकार पर पैशन का बोझ बढ़ेगा। कुर्सी भरेगी, युवा बसेगा, देश बसेगा।

परमाणु नहीं। ठेके पर काम करने वाले युवाओं का शोषण होता है, उन्हें परिवार चलाने का पर्याप्त पैसा नहीं मिलता, न भविष्य की सुरक्षा मिलती है। ये 55 लाख खाली पद अगर कक्षा 10 के बाद 'Dual Work System' से भरे जाएँ तो 18 साल का युवा अप्रेंटिस बनकर 20 हजार कमा लेगा। न वो बेरोजगार कहलाएगा, न सरकार पर पैशन का बोझ बढ़ेगा। कुर्सी भरेगी, युवा बसेगा, देश बसेगा।

परमाणु नहीं। ठेके पर काम करने वाले युवाओं का शोषण होता है, उन्हें परिवार चलाने का पर्याप्त पैसा नहीं मिलता, न भविष्य की सुरक्षा मिलती है। ये 55 लाख खाली पद अगर कक्षा 10 के बाद 'Dual Work System' से भरे जाएँ तो 18 साल का युवा अप्रेंटिस बनकर 20 हजार कमा लेगा। न वो बेरोजगार कहलाएगा, न सरकार पर पैशन का बोझ बढ़ेगा। कुर्सी भरेगी, युवा बसेगा, देश बसेगा।

परमाणु नहीं। ठेके पर काम करने वाले युवाओं का शोषण होता है, उन्हें परिवार चलाने का पर्याप्त पैसा नहीं मिलता, न भविष्य की सुरक्षा मिलती है। ये 55 लाख खाली पद अगर कक्षा 10 के बाद 'Dual Work System' से भरे जाएँ तो 18 साल का युवा अप्रेंटिस बनकर 20 हजार कमा लेगा। न वो बेरोजगार कहलाएगा, न सरकार पर पैशन का बोझ बढ़ेगा। कुर्सी भरेगी, युवा बसेगा, देश बसेगा।

परमाणु नहीं। ठेके पर काम करने वाले युवाओं का शोषण होता है, उन्हें परिवार चलाने का पर्याप्त पैसा नहीं मिलता, न भविष्य की सुरक्षा मिलती है। ये 55 लाख खाली पद अगर कक्षा 10 के बाद 'Dual Work System' से भरे जाएँ तो 18 साल का युवा अप्रेंटिस बनकर 20 हजार कमा लेगा। न वो बेरोजगार कहलाएगा, न सरकार पर पैशन का बोझ बढ़ेगा। कुर्सी भरेगी, युवा बसेगा, देश बसेगा।

परमाणु नहीं। ठेके पर काम करने वाले युवाओं का शोषण होता है, उन्हें परिवार चलाने का पर्याप्त पैसा नहीं मिलता, न भविष्य की सुरक्षा मिलती है। ये 55 लाख खाली पद अगर कक्षा 10 के बाद 'Dual Work System' से भरे जाएँ तो 18 साल का युवा अप्रेंटिस बनकर 20 हजार कमा लेगा। न वो बेरोजगार कहलाएगा, न सरकार पर पैशन का बोझ बढ़ेगा। कुर्सी भरेगी, युवा बसेगा, देश बसेगा।

परमाणु नहीं। ठेके पर काम करने वाले युवाओं का शोषण होता है, उन्हें परिवार चलाने का पर्याप्त पैसा नहीं मिलता, न भविष्य की सुरक्षा मिलती है। ये 55 लाख खाली पद अगर कक्षा 10 के बाद 'Dual Work System' से भरे जाएँ तो 18 साल का युवा अप्रेंटिस बनकर 20 हजार कमा लेगा। न वो बेरोजगार कहलाएगा, न सरकार पर पैशन का बोझ बढ़ेगा। कुर्सी भरेगी, युवा बसेगा, देश बसेगा।

परमाणु नहीं। ठेके पर काम करने वाले युवाओं का शोषण होता है, उन्हें परिवार चलाने का पर्याप्त पैसा नहीं मिलता, न भविष्य की सुरक्षा मिलती है। ये 55 लाख खाली पद अगर कक्षा 10 के बाद 'Dual Work System' से भरे जाएँ तो 18 साल का युवा अप्रेंटिस बनकर 20 हजार कमा लेगा। न वो बेरोजगार कहलाएगा, न सरकार पर पैशन का बोझ बढ़ेगा। कुर्सी भरेगी, युवा बसेगा, देश बसेगा।

## विचार बिन्दु

स्मृति पीछे दृष्टि डालती है और आशा आगे। -रामचंद्र टंडन

# राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं की नैतिकता संकट में

राजस्थान में चिकित्सा तंत्र आज घोर संकट की तस्वीर पेश कर रहा है, और विशेषकर राजधानी जयपुर में इससे अनछूटा नहीं है। हाल के खुलासों, मीडिया रिपोर्टों और शोषों ने यह प्रमाणित किया है कि जहाँ चिकित्सा का मूल उद्देश्य रोगी की भलाई होना चाहिए, वहीं कहीं-कहीं इलाज का लक्ष्य लाभ बन गया है। बड़े निजी अस्पतालों में अनावश्यक भर्ती, जांच और ऑपरेशनों की बढ़ती प्रवृत्ति, बीमा घोटाले, दवा उद्योग तथा चिकित्सकों के बीच सांड-गाठ और अंग-तस्करी जैसी बीभत्स घटनाएँ रोगी-हित की हिफाजत करने वाली व्यवस्था की मौलिक कमजोरियों को उजागर करती हैं। राजस्थान के ग्रामीण व शहरी दोनों हिस्सों में यह संकट अलग-अलग रूपों में उभर रहा है और जयपुर, जहाँ चिकित्सा सुविधाओं का केंद्र है, इन समस्याओं के सामने एक सूक्ष्म लेकिन निर्णायक उदाहरण प्रस्तुत करता है।

अस्पतालों में होने वाले ऑपरेशनों की असामान्य रूप से ऊँची सुविचों जैसे हायटेरेक्टॉमी, सी-सेक्शन, हृदय सर्जरी और अर्थ्रोप्लास्टी केवल चिकित्सकीय प्रवृत्ति का मामला नहीं है; यह उस व्यवस्था का संकेत है जिसमें आर्थिक प्रोत्साहन चिकित्सकीय निर्णयों में घुस आते हैं। जयपुर जैसे महानगरों में उच्च-प्रोफाइल निजी संस्थान और कुछ वरिष्ठ चिकित्सक जिनको पारिश्रमिक कई गुना होती है, का प्रभाव निर्णय-प्रक्रिया पर दिखाई देता है। राजधानी के पास उपलब्ध विशेषज्ञता और उन्नत सुविधाएँ ग्रामीण मरीजों को आकर्षित करती हैं, पर साथ ही अनावश्यक प्रक्रियाओं का जोखिम भी बढ़ जाता है-क्योंकि दूर-दराज के लोग मामूली बीमारी के लिए बड़े शहर आकर विशेषज्ञों पर निर्भर हो जाते हैं और अक्सर उनके पास विकल्पों की कमी रहती है।

बीमा प्रणाली, जो प्रभुत्व: आर्थिक सुरक्षा और चिकित्सा तक पहुँच का जरिया है, कई मामलों में भरोसे के संकट में बदल चुकी है। जयपुर के कुछ केंसों में क्लेम अस्वीकार किए जाने, प्रक्रियागत बाधाओं और विवादित बिलिंग के आरोप सामने आए हैं, जिनसे लोगों का विश्वास मंजला हुआ है। कोविड-19 के समय में देशव्यापी जैसे कुछ आंदोलनों ने यह दिखाया कि आपातकालीन परिस्थितियों में भी पारदर्शिता लचीली हो सकती है। राजधानी के आस-पास के जिलों से आई शिकायतें इस बात का संकेत हैं कि बीमा और निजी अस्पताल के बीच के व्यवहार ने विशेषकर मध्यम आय वर्ग और गरीब रोगियों की बचत पर चोट की है।

लैब व डायग्नोस्टिक रिपोर्टों की विश्वसनीयता पर उठते सवाल और कुछ पैथोलॉजी प्रयोगशालाओं के खतरनाक खेल ने चिकित्सा विज्ञान के आधार को भी हिला दिया है। जयपुर में किए गए कुछ छापे और जांचें इस ओर इशारा करती हैं कि नकदी लेनदेन और अनियमित रिपोर्टिंग जैसी प्रथाएँ मौजूद रही हैं। जब परीक्षण ही संदिग्ध हों तो निदान और उपचार दोनों प्रभावित होते हैं। छोटे शहरों व गांवों के मरीज जो जयपुर की लैबों पर भरोसा कर रिपोर्ट बनाते हैं, वे गलत रिपोर्ट के कारण अनावश्यक दवाइयों और अतिरिक्त प्रक्रियाओं के शिकार बन सकते हैं।

फार्मा उद्योग और चिकित्सकीय पेशे के बीच हितों का टकराव भी गंभीर रूप ले चुका है। ब्रांडेड दवाओं के प्रचार और कॉर्पोरेट प्रस्तुतियों के बहाने चिकित्सकीय निर्णयों पर प्रभाव पड़ने की आशंका है। जयपुर की कॉर्पोरेट क्लिनिक-हब संस्कृति में, जहां दवा कंपनियों की गतिविधियाँ ज्यादा दिखाई देती हैं, मरीजों को महँगी दवाएँ दी जाने के आरोप उभरते रहे हैं जबकि जेनरिक विकल्प उपलब्ध और प्रभाव्य होता है। अस्पतालों का दवा और उपकरण पर मार्जिन तथा बिलिंग में पारदर्शिता का अभाव राजधानी के मध्यम और निम्न आय वर्ग परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालता है।

सबसे भयावह पक्ष अंग-तस्करी और मानव शोषण के मामले हैं। राजस्थान के सीमांत इलाकों से जुड़े कुछ नेटवर्क ने कभी-कभी जयपुर के अस्पतालों व क्लिनिकों को भी अपने कामकाज के लिए उपयोग किया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि महानगर का चिकित्सा-इकोसिस्टम पसरायी नेटवर्क के संपर्क में आ सकता है। नौकरी या इलाज के नाम पर बहलाकर लाने, फर्जी भर्ती और परीक्षण करार अंगों के अवैध व्यापार में डालने जैसे क्रूर केवल कानूनी अपराध ही नहीं, बल्कि समाज की नैतिकता पर चोट है। ऐसे मामलों में अस्पतालों, चिकित्सकों और एजेंटों के आपसी नेटवर्क का होना चिंत्नीय है और आपसी पहचानों की सुरक्षा पर गहरा असर डालता है।

नियमों और नियामक संस्थाओं की कमजोरी इन कुप्रथाओं को बढ़ाने का एक बड़ा कारण है। मेडिकल शिक्षा और अस्पतालों के लाइसेंसिंग पर नजर रखने वाली संस्थाएँ, जिनसे मानक और गुणवत्ता की उम्मीद रहती है, कई बार संसाधन की कमी, अनुपालन की लापरवाही या राजनीतिक दबाव के कारण कड़ी निगरानी नहीं कर पाती। जयपुर में नई कानूनी और नियामक संस्थाओं की कमजोरी इन कुप्रथाओं को बढ़ाने का एक बड़ा कारण है। मेडिकल शिक्षा और अस्पतालों के लाइसेंसिंग पर नजर रखने वाली संस्थाएँ, जिनसे मानक और गुणवत्ता की उम्मीद रहती है, कई बार संसाधन की कमी, अनुपालन की लापरवाही या राजनीतिक दबाव के कारण कड़ी निगरानी नहीं कर पाती। जयपुर में नई

पैथोलॉजी और डायग्नोस्टिक लैब्स का प्रमाण और नियमित निरीक्षण तेज करना होगा। केवल प्रमाणित लैबों को सरकारी या बीमा से जुड़े मामलों की रिपोर्ट करने की अनुमति देनी चाहिए, और अनियमितता पाई जाने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई व लाइसेंस रद्द करने की व्यवस्था होनी चाहिए। जयपुर में नियमित आकस्मिक निरीक्षण, सैपल-ऑडिट और नागरिक शिकायत तंत्र प्रभावशीलता बढ़ाने के उपाय हैं।

निजी मेडिकल क्लिनिक और डायग्नोस्टिक सेंटर के त्वरित उदय ने मानकीकरण और नियमित निरीक्षण की आवश्यकता को और बल दिया है। पारदर्शिता की कमी और नियमों का ढीलापन ही उन प्रथाओं को पोषित करता है जो चिकित्सा की मूल नैतिकता को चुनौती देती हैं।

इन चुनौतियों से निपटने के लिए बहुस्तरीय और तटस्थ सुभार आवश्यक हैं। सबसे पहले, चिकित्सा और अस्पतालों के वित्तीय व्यवहार पर पारदर्शिता अनिवार्य की जानी चाहिए। डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स को सार्वभौमिक व केंद्रीकृत बनाया जाना चाहिए ताकि हर जांच, इलाज और सर्जरी का रिकॉर्ड टिकाऊ और सार्वजनिक ऑडिट के लिए उपलब्ध रहे। जयपुर में डिजिटल इंटीग्रेशन मॉडल को पूरे राज्य में फैलाया जा सकता है। राज्य सरकार और लोक स्वास्थ्य विभाग को इस दिशा में शीघ्र कदम उठाने चाहिए। इससे फर्जी रिपोर्ट, बिना सहमति के सर्जरी और नकली क्लेम की पहचान में मदद मिलेगी।

क्लिनिकल निर्णयों पर बाहरी निगरानी और नियमित क्लिनिकल ऑडिट लागू किया जाना चाहिए। जयपुर जैसे बड़े शहरों में उच्च-जोखिम वाले ऑपरेशनों के लिए स्वतंत्र चिकित्सकीय समितियों से पूर्व अनुमति जैसी प्रक्रियाएँ लागू कर के अनावश्यक सर्जरी घटाई जा सकती है। रेफरल और अन्य आर्थिक प्रोत्साहनों की जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए और इस तरह के भुगतान के खुलासे पर सख्त सीमाएँ लगनी चाहिए।

पैथोलॉजी और डायग्नोस्टिक लैब्स का प्रमाण और नियमित निरीक्षण तेज करना होगा। केवल प्रमाणित लैबों को सरकारी या बीमा से जुड़े मामलों की रिपोर्ट करने की अनुमति देनी चाहिए, और अनियमितता पाई जाने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई व लाइसेंस रद्द करने की व्यवस्था होनी चाहिए। जयपुर में नियमित आकस्मिक निरीक्षण, सैपल-ऑडिट और नागरिक शिकायत तंत्र प्रभावशीलता बढ़ाने के उपाय हैं।

फार्मा कंपनियों और चिकित्सा पेशे के बीच हित-टकराव पर कड़ा नियंत्रण लागू होना चाहिए। चिकित्सकों को जेनरिक दवाओं को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित किया जाए और प्रलोभन स्वीकारने वालों पर सख्त दंडात्मक प्रावधान हों। मेडिकल शिक्षा में नैतिकता और पारदर्शिता की अनिवार्य ट्रेनिंग दी जानी चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियाँ पेशेवर ईमानदारी को प्राथमिकता दें। जयपुर के मेडिकल कॉलेज और प्रशिक्षण संस्थान इस पाठ्यक्रम को मॉडल बनाकर पूरे राज्य में प्रसारित कर सकते हैं।

अंग-तस्करी व मानव शोषण के मामलों के लिए त्वरित और विशेष जांच-प्रक्रियाएँ जरूरी हैं। पुलिस-स्वास्थ्य विभाग समन्वय को मजबूत किया जाए और पीडितों की सुरक्षा हेतु संवेदनशील हेल्पलाइन व संरक्षण-प्रणालियाँ लागू की जाएँ। भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी व पंजीकृत करना होगा ताकि रोजगार के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी पर अंकुश लगे। जयपुर में समर्पित कैपेन और जागरूकता कार्यक्रम निश्चित रूप से प्रभाव्य साबित हो सकते हैं, विशेषकर जब स्थानीय सामाजिक संस्थाएँ और पंचायतें साथ दें।

मरीजों की जागरूकता और शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करना अनिवार्य है। मरीजों को इलाज के विकल्प, अनुमानित लागत, संभावित जोखिम और वैकल्पिक उपचारों की स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। प्रभाव्य नागरिक शिकायत निवारण पैनल जिनमें विशेषज्ञों और नागरिक समाज के प्रतिनिधि हों, तेज और निष्पक्ष निर्णय दें। स्वतंत्र मीडिया व जनजागरूकता अभियानों की भूमिका को बढ़ावा देना होगा क्योंकि खबरों और सार्वजनिक खुलासों ने कई कुख्यात प्रकरणों को उजागर किया है। जयपुर के स्थानीय मीडिया और नागरिक मंच इस दिशा में सक्रिय रहकर राज्यव्यापी प्रभाव पैदा कर सकते हैं।

राजस्थान में चिकित्सा तंत्र की गरिमा और समाज का विश्वास तभी बहाल होगा जब नीति-निर्माण, कड़ा नियमन, तकनीकी पारदर्शिता और नैतिकता पर एक साथ जोर दिया जाए। अस्पताल और डॉक्टर सिर्फ बीमारी का उपचारक नहीं, समाज के भरोसे के रखवाले भी हैं। जब तक यह भरोसा लौटकर नहीं आता, तब तक स्वास्थ्य तंत्र में व्यापक रूप से जोखिम बना रहेगा और मरीजों, परिवारों तथा समाज पर अघात, तब तक चलेगा। जयपुर में समर्पित कैपेन और जागरूकता कार्यक्रम निश्चित रूप से प्रभाव्य साबित हो सकते हैं, विशेषकर जब स्थानीय सामाजिक संस्थाएँ और पंचायतें साथ दें।

-अतिथि संपादक, अविनाश जोशी,

वरिष्ठ पत्रकार एवं कॉर्पोरेट सलाहकार

# प्रदेश में तृतीय श्रेणी शिक्षकों को छह साल से पदोन्नति का इंतजार

राज्य सरकार की 5 जुलाई तक तबादलों से हटाई रोक को इस बार भी इन शिक्षकों पर लागू नहीं किया है

इसे में पद और स्थान दोनों परिवर्तनों का लाभ नहीं मिलने से करीब 1.22 लाख शिक्षक पदोन्नति व तबादला नीति के दो पाठों में पिसते महसूस कर रहे हैं। शिक्षक नेता मोहर सिंह सलावद ने बताया कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों की पदोन्नति भी छह साल से अटक गई है। अतिरिक्त विषय से स्नातक डिग्री की वैधता को लेकर चल रहे न्यायिक विवाद की वजह से लगभग 30 हजार शिक्षकों की पदोन्नति नहीं हो पा रही। शिक्षक संघ रसदटा का आरोप है कि सरकार के हीने रवैये की वजह से ही मामला कोर्ट में ढीला चल रहा है। यदि ग्रेड थर्ड शिक्षक पदोन्नत होते तो द्वितीय थर्ड श्रेणी शिक्षक नियुक्त होने पर उन्हें तबादलों का लाभ भी मिल जाता। राज्य में कार्यरत तृतीय श्रेणी शिक्षकों के अंतिम बार तबादले 2018 में हुए थे। उसके बाद से सरकारें तबादला नीति लागू करने का हवाला देते हुए उसे लगातार टाल रही हैं। इससे दूरदराज के इलाके में लंबे समय से नियुक्त लगभग 1 लाख शिक्षकों का तबादलों का इंतजार खत्म नहीं हो रहा है। प्रतिबंधित 10 जिलों में तो कई शिक्षक 15-15 साल से घर वापसी का इंतजार कर रहे हैं।

कबीरकानेर, (निर्स)। राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षक पद सोपान में सबसे अंतिम पायदान पर नियुक्त तृतीय श्रेणी शिक्षकों के साथ सरकार का थर्ड ग्रेड टॉचर लगातार जारी है। राज्य सरकार की 5 जुलाई तक तबादलों से हटाई रोक को इस बार भी इन शिक्षकों पर लागू नहीं किया है। उधर 6 साल से इनकी पदोन्नति भी कानूनी पचड़े में फंसी हुई

राज्य सरकार की 5 जुलाई तक तबादलों से हटाई रोक को इस बार भी इन शिक्षकों पर लागू नहीं किया है

राज्य सरकार की 5 जुलाई तक तबादलों से हटाई रोक को इस बार भी इन शिक्षकों पर लागू नहीं किया है

राज्य सरकार की 5 जुलाई तक तबादलों से हटाई रोक को इस बार भी इन शिक्षकों पर लागू नहीं किया है

राज्य सरकार की 5 जुलाई तक तबादलों से हटाई रोक को इस बार भी इन शिक्षकों पर लागू नहीं किया है

राज्य सरकार की 5 जुलाई तक तबादलों से हटाई रोक को इस बार भी इन शिक्षकों पर लागू नहीं किया है

राज्य सरकार की 5 जुलाई तक तबादलों से हटाई रोक को इस बार भी इन शिक्षकों पर लागू नहीं किया है

राज्य सरकार की 5 जुलाई तक तबादलों से हटाई रोक को इस बार भी इन शिक्षकों पर लागू नहीं किया है

राज्य सरकार की 5 जुलाई तक तबादलों से हटाई रोक को इस बार भी इन शिक्षकों पर लागू नहीं किया है

राज्य सरकार की 5 जुलाई तक तबादलों से हटाई रोक को इस बार भी इन शिक्षकों पर लागू नहीं किया है

राज्य सरकार की 5 जुलाई तक तबादलों से हटाई रोक को इस बार भी इन शिक्षकों पर लागू नहीं किया है

राज्य सरकार की 5 जुलाई तक तबादलों से हटाई रोक को इस बार भी इन शिक्षकों पर लागू नहीं किया है

राज्य सरकार की 5 जुलाई तक तबादलों से हटाई रोक को इस बार भी इन शिक्षकों पर लागू नहीं किया है

राज्य सरकार की 5 जुलाई तक तबादलों से हटाई रोक को इस बार भी इन शिक्षकों पर लागू नहीं किया है

## कई वर्षों बाद अशोक गहलोत 10 जनपथ में प्रवेश पा सके

राजीव गांधी नैशनल रिलीफ फण्ड की बैठक थी तथा कई पुराने नेता, जैसे पवन बंसल, मुकुल वासनिक, सलमान खुर्शीद, जनार्दन द्विवेदी व गहलोत इस फण्ड के पुराने सदस्य हैं

-रेणु मिश्र-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 25 जून। राजस्थान में हुए चर्चित राजनीतिक विद्रोह के बाद, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उस समय की कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ बगावत की थी, तब से गांधी परिवार और 10 जनपथ की नजरों में वे "अवांछित" हो गए थे। लेकिन आज, कई वर्षों के अंतराल के बाद, अशोक गहलोत ने 10 जनपथ में प्रवेश किया।

सूत्रों के अनुसार, यह बैठक राजीव गांधी राष्ट्रीय राहत कोष की थी, जिसके सदस्य कई वरिष्ठ नेता हैं। इनमें पवन बंसल, मुकुल वासनिक, सलमान खुर्शीद, जनार्दन द्विवेदी और अशोक गहलोत शामिल हैं।

एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि इस ट्रस्ट की बैठक कई वर्षों से नहीं हुई थी और कुछ तकनीकी समस्याओं को दूर करना आवश्यक था।

बैठक में पवन बंसल द्वारा कुछ नए प्रावधान जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया, जबकि कुछ पुराने प्रावधान हटाने की मांग भी की गई, जिसे बैठक में स्वीकार

- कई सालों से बैठक नहीं हुई थी, अतः कई तकनीकी कमियां उभर आई थीं, जिन्हें दूर करना आवश्यक हो गया था।
- गहलोत व गांधी परिवार में काफी दूरियां हो गई हैं। अतः गहलोत का बैठक में भाग लेने का न्यौता बड़ी बात है, पर, इतनी बड़ी भी बात नहीं है, जितना गहलोत समर्थक ढिंढोरा पीट-पीट कर प्रचारित कर रहे हैं।
- यह भी सच है कि गहलोत काफी समय से गांधी परिवार से मिलने के इच्छुक थे, पर, बात नहीं बन रही थी।
- गहलोत किसी भी तरह से एआईसीसी में एडजस्ट होना चाह रहे हैं, पर, प्रयासों को सफलता नहीं मिल रही है।
- यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि राजस्थान के प्रभारी रंधावा ने के.सी. वेणुगोपाल से मुलाकात की और राजस्थान में पार्टी में काफी रद्दोबदल पर काफी चर्चा हुई।
- सबसे बड़ा परिवर्तन जो प्रस्तावित है, वह है नए प्रदेशाध्यक्ष की नियुक्ति, डोटोसरा के स्थान पर।
- डोटोसरा को रंधावा के अलावा के.सी. वेणुगोपाल का समर्थन प्राप्त है, पर, दूसरी ओर यह भी अनिवार्य है कि नए प्रदेशाध्यक्ष की नियुक्ति अति अनिवार्य है, राजस्थान में, अगर पार्टी अगले चुनाव में जीतना चाहती है।

कर लिया गया।

गांधी परिवार और अशोक गहलोत

के बीच विश्वास की कमी होने के

बावजूद, ट्रस्ट की बैठक में शामिल होने

के लिए भेजे गए निमंत्रण को मीडिया

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## भाजपा में भारी उथल-पुथल होने के आसार नज़र आ रहे हैं

मुख्य टारगेट हैं मध्य प्रदेश के मु.मंत्री मोहन यादव और इस परिवर्तन की शृंखला में यूपी के मु.मंत्री को घेरा जा रहा है तथा बिहार के मु.मंत्री सम्राट चौधरी पर भी सोशल एक्टिविस्ट भारत भूषण तिवाड़ी हत्याकांड को गंभीरता से न लेने का आरोप लगाया जा रहा है

-श्रीनंद झा-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 25 जून। पिछले कुछ सप्ताहों में भाजपा के भीतर असाधारण घटनाक्रम देखने को मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के परिवार से जुड़े भूमि सौदों की खबरों के बाद भाजपा और आरएसएस नेताओं ने उनके बचाव में अपेक्षाकृत चुपकी साह रखा है। राजस्थान में संघ परिवार का प्रचार तंत्र मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की बहुत धार्मिक होने की छवि की भी बहुत सक्रिय रूप से खिलाफत नहीं कर रहा है। बिहार में सहयोगी दल के नेता उपेन्द्र कुशवाहा तथा पूर्व केन्द्रीय मंत्री

- अयोध्या के राम मंदिर में भी चढ़ावे में पैसे की गड़बड़ी में भाजपा के दो ग्रुप आपस में आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं।
- ऐसे माहौल में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन भी संगठन में तब्दिलियाँ कर रहे हैं तथा पार्टी का पब्लिसिटी विभाग, अपने नेताओं की छवि को बचाने का कोई खास प्रयास नहीं कर रहा।

अश्विनी चौबे सहित, कई वरिष्ठ नेता 28 वर्षीय सामाजिक कार्यकर्ता भारत भूषण तिवाड़ी की हत्या से जुड़े मामले को संभालने के तरीके को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर निशाना

साथ रहे हैं। अयोध्या मंदिर में धन के कथित गबन के मामले में भी भाजपा नेतृत्व का एक गुट दूसरे गुट के खिलाफ खड़ा दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर, (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## शिक्षक भर्ती-2025 की उत्तर कुंजी के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका

जयपुर, 25 जून। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित शिक्षक भर्ती-2025 के लेवल प्रथम की परीक्षा में विवादित प्रश्न-उत्तर से जुड़े मामले में अंतिम

- याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई 29 जून को होगी।

उत्तर कुंजी को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता ममता यादव व अन्य ने याचिका दायर कर हाईकोर्ट से नियुक्तियों पर रोक लगाने की गुहार की है। याचिका पर हाईकोर्ट में 29 जून को सुनवाई होगी।

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सेनी ने बताया कि भर्ती के इन विवादित प्रश्न-उत्तर पर विषय विशेषज्ञों की एक स्वतंत्र कमेटी बनाई जाए। वहीं भर्ती का दुबारा से परिणाम जारी किया जाए और तब तक नियुक्तियों पर रोक लगाई जाए। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## लोक अदालत ने नीलामी रद्द करना गलत माना, हाउसिंग बोर्ड पर जुर्माना लगाया

जयपुर, 25 जून। स्थायी लोक अदालत, महानगर प्रथम ने शहर के मानसरोवर में दुकानों की नीलामी आयोजित करने के बाद, उसे बाद में निरस्त करने को गलत मानते हुए उसे रद्द कर दिया है। इसके साथ ही, अदालत ने आवासन मंडल पर 42 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है, तथा अदालत ने नीलामी में सफल बोलीदाता के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित करने को कहा है।

- अदालत ने सफल बोलीदाता के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित करने के आदेश भी दिए।

पोटासीन अधिकारी मनोज कुमार सहारिया और सदस्य बलदेवराज बेनीवाल ने यह आदेश प्रवीण कुमार शर्मा के परिवार पर दिए।

अदालत ने कहा कि आवासन मंडल की 16 सितंबर 2019 की अधिसूचना में स्पष्ट प्रावधान है कि एकल बोलीदाता होने के आधार पर नीलामी निरस्त नहीं की जाएगी। बोर्ड ने 28 जनवरी 2014 के आदेशों के तहत नीलामी रद्द की, जबकि इसके बाद की अधिसूचना और आदेश इसके खिलाफ हैं।

ऐसे में पहले के आदेश को बाद के आदेशों पर वरीयता नहीं दी जा सकती। इसलिए आवासन मंडल का नीलामी को निरस्त करना अवैध, अनुचित और मनमाना कृत्य है।

## ‘पासपोर्ट होना, नागरिकता का प्रमाण नहीं है’

विदेश मंत्रालय के बड़े अफसर के अनुसार, पासपोर्ट केवल “यात्रा” के लिए तैयार किया गया दस्तावेज है

-जाल खंबाता-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 25 जून। इस सप्ताह तीखी ऑनलाइन बहस के बाद, सरकार के सूत्रों ने जोर देकर कहा कि पासपोर्ट नागरिकता का सबूत नहीं है। बहस की शुरुआत विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी की उस टिप्पणी से हुई, जिसमें उन्होंने कहा था कि पासपोर्ट केवल एक यात्रा दस्तावेज है।

अब तक बहुत से लोग मानते थे कि पासपोर्ट, धारक को भारतीय नागरिक के रूप में मान्यता देता है। लेकिन अब सरकार ने कहा है कि कानूनी रूप से ऐसा नहीं है। इसके बाद पासपोर्ट के उद्देश्य, उसकी कानूनी स्थिति और व्यवहारिक उपयोग को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है।

विवाद तब शुरू हुआ, जब विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि पासपोर्ट “पूरी तरह से एक यात्रा दस्तावेज” है और इसे नागरिकता के सबूत के तौर पर नहीं माना जा सकता। अधिकारी ने जोर देकर कहा कि इसे जारी करने का यह मतलब नहीं है कि धारक को भारतीय नागरिकों के लिए बनी कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच हो ही जायेगी तथा उनका लाभ मिल ही जायेगा।

सरकार यह पहले ही कह चुकी है कि आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र भी नागरिकता का प्रमाण नहीं है।

- पासपोर्ट के होने से कोई भी व्यक्ति, भारतीय नागरिकों के लिए दी गई कई “वेलफेयर स्कीम्स” का हकदार नहीं हो जाता।
- सरकार, पहले ही यह घोषणा कर चुकी है कि आधार कार्ड व वोटर आईडेंटिटी कार्ड को नागरिकता के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- इसके विपरीत यह तर्क दिया गया है कि पासपोर्ट भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है, पूरी तरह बैंक-ग्राउण्ड जानकारी प्राप्त करने के बाद, जिसमें पुलिस वैरिफिकेशन भी शामिल है तथा इस प्रक्रिया से यह स्थापित हो जाता है कि पासपोर्टधारी भारत का नागरिक है।
- एक तर्क यह भी दिया जा रहा है कि कई बार गैर नागरिकों को भी पासपोर्ट जारी किया गया, अगर ऐसा करने से कूटनीतिक लाभ हो रहा हो और विशेष परिस्थितियों हों।
- बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्णय के अनुसार, 1967 के पासपोर्ट एक्ट की धारा 20 में यह स्पष्ट लिखा है कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है।

इसके बाद एकसुर पर गंभीर और व्यापक टिप्पणियों की बाढ़ आ गई। “नागरिकता का प्रमाण नहीं? यह तो बेटुकी बात है।”

कई लोगों ने कहा कि पासपोर्ट केवल भारत सरकार द्वारा जारी किया

जाता है और इसके लिए विस्तृत जाँच-पड़ताल की जाती है। इसमें किसी व्यक्ति के निवास संबंधी विवरण का पुलिस द्वारा भौतिक सत्यापन भी शामिल होता है। पासपोर्ट में स्पष्ट रूप (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## करोड़ों एंड्रॉयड मोबाइल फोन्स में एक्सलरोमीटर भूकंप की प्राइमरी कंपनी को महसूस करते हैं

और गूगल इन सभी मोबाइल फोन्स के कंपनी के आधार पर आने वाले भूकंप का लोकेशन व साइज़ का अच्छा अंदाज़ लगा लेते हैं

-जाल खंबाता-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 25 जून। वेनेजुएला में लाखों लोगों को उनके एंड्रॉयड फोन पर जमीन हिलने से कुछ क्षण पहले चेतावनी संदेश मिला।

यह चेतावनी इस दक्षिण अमेरिकी देश में जबरदस्त भूकंप आने से कुछ सैकंड पहले ही मिली थी। हालांकि, यह समय बहुत कम था, लेकिन इन कुछ सैकंड ने एक बार फिर दुनिया भर में इस सवाल को चर्चा का विषय बना दिया- क्या तकनीक प्राकृतिक आपदाओं के समय लोगों को जान बचाने में मदद कर सकती है?

विशेषज्ञों का जवाब है, हां, लेकिन एक महत्वपूर्ण शर्त के साथ।

- तकनीकी विशेषज्ञों के इस अनुभव ने यह स्थापित कर दिया कि भूकंप का आना तो साइंस नहीं रोक सकती, पर, जल्दी चेतावनी मिलने से भूकंप से होने वाली हानि को जरूर कम किया जा सकता है।

गूगल ने भूकंप की भविष्यवाणी नहीं की थी। इसके बजाय, उसने भूकंप के शुरुआती संकेतों को पहचान लिया और तेज झटके आने से पहले प्रभावित क्षेत्र के लोगों को चेतावनी भेज दी। रिपोर्टों के अनुसार, गूगल के एंड्रॉयड अर्थक्वैक अलर्ट सिस्टम ने शुरुआती भूकंपीय गतिविधि का पता लगाया और विनाशकारी झटके पहुंचने से पहले आसपास के उपयोगकर्ताओं को चेतावनी भेज दी। यह तकनीक

अरबों एंड्रॉयड स्मार्टफोन पर आधारित है, जिनमें लगे मोशन सेंसर जमीन की बेहद हल्की हलचल को भी महसूस कर सकते हैं। एचआर एनेक्सी की बीओटीएस.एआई के निदेशक निखर अरोड़ा ने कहा कि वेनेजुएला की यह घटना दिखाती है कि भूकंप की प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली कितनी विकसित हो चुकी है। उन्होंने कहा, “जैसा कि बहुत से

लोग मानते हैं, गूगल ने भूकंप की भविष्यवाणी नहीं की थी। उसने केवल भूकंप के शुरुआती संकेतों का पता लगाया और तेज झटके शुरू होने से पहले चेतावनी जारी कर दी।”

उन्होंने बताया कि एंड्रॉयड फोन एक विशाल सेंसर नेटवर्क की तरह काम करते हैं। इनमें लगे एक्सलरोमीटर प्राथमिक भूकंपीय तरंगों, यानी पी-वेव्स को पहचान लेते हैं, जो अधिक विनाशकारी एस-वेव्स की तुलना में तेजी से यात्रा करती हैं।

अरोड़ा ने कहा, “जब बड़ी संख्या में उपकरणों में एक जैसा पैटर्न दिखाई देता है, तो गूगल के एल्गोरिथम भूकंप के स्थान और तीव्रता का अनुमान लगाते हैं (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## प्रधानमंत्री 27 जून को सेशल्स जार्यंगे

नई दिल्ली, 25 जून। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हिन्द महासागर के खूबसूरत द्वीपीय देश सेशल्स की स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लेने के लिए शनिवार को तीन दिन की यात्रा पर सेशल्स जाएंगे।

विदेश मंत्रालय ने आज यहां बताया कि प्रधानमंत्री 27-29 जून को सेशल्स की राजकीय यात्रा करेंगे। वे रविवार को ‘विशिष्ट अतिथि’ के तौर पर सेशल्स के

- वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री ने पिछली बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। इस समारोह में भारतीय रक्षा बलों की एक टुकड़ी और भारतीय नौसेना के दो जहाज हिस्सा लेंगे।

विदेश मंत्रालय के अनुसार, अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हर्मिनी (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

-कार्यालय संवाददाता- जयपुर, 25 जून। राजस्थान हाईकोर्ट ने सीकर कलेक्टर व श्रीमाधोपुर उपखंड अधिकारी की ओर से 12 जून को जारी उस आदेशों पर रोक लगाई है, जिसमें रूपपुरा-उदलवास के खसरा नंबर 68 से 74 तक के

पिछले कई वर्षों से अदालत में लंबित चल रहा है। हाईकोर्ट ने सरदार सिंह कुमावत व रामचंद्र प्रजापति की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। इस प्रकरण में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अनुराग कलवाटिया पैरवी के लिए पेश हुए थे। न्यायाधीश अनुरूप सिंघो ने जिला कलेक्टर, उपखंड अधिकारी श्रीमाधोपुर व अन्य

- ज्ञात रहे कि मुख्यमंत्री की जनसुनवाई में रूपपुरा-उदलवास के खसरा नंबर 68 से 74 की भूमि को लेकर एक पक्ष द्वारा तथ्य छिपाकर शिकायत की गई थी, जिस पर सीएमओ ने कार्रवाई के निर्देश दिए थे।

पक्षकारों को इस मामले की अगली सुनवाई, 11 अगस्त को पेश होने के लिए कहा है। साथ ही, अदालत ने आदेश दिए हैं कि राज्य सरकार अथवा जिला प्रशासन याचिकाकर्ता के खिलाफ फिलहाल कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेंगे। अधिवक्ता अनुराग कलवाटिया ने अदालत को बताया था कि इस मामले में याचिकाकर्ता सरदार सिंह कुमावत व

रामचंद्र प्रजापति के पक्ष में 15 अक्टूबर 2024 को अतिरिक्त कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) नीमकाथाना ने यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिए थे। ये तथ्य शिकायतकर्ता द्वारा मुख्यमंत्री की जनसुनवाई में उजागर नहीं किए गए थे।

## राहुल गांधी ने खेद जताया, मानहानि का केस समाप्त

जबलपुर, 25 जून। मध्य प्रदेश की सियासत का एक लंबा और चर्चित कानूनी विवाद आखिरकार सौहार्दपूर्ण मोड़ पर गुरुवार को समाप्त हो गया। दरअसल, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पुत्र कार्तिकेय सिंह चौहान के बीच चल रहा मानहानि का मामला पूरी तरह सुलझ गया है। सुनवाई के दौरान राहुल गांधी ने

- केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के पुत्र कार्तिकेय सिंह ने राहुल गांधी का खेद स्वीकार किया व केस समाप्त करने की सहमति दी।

अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में आवेदन दायर कर इस घटना पर गहरा खेद व्यक्त किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि उस वक्त भूलवश उनके मुँह से कार्तिकेय सिंह चौहान का नाम निकल गया था,

जबकि उनका आशय किसी अन्य व्यक्ति से था। अपने बयान पर खेद जताते हुए उन्होंने माननीय न्यायालय से राहत की मांग की। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## अगले चुनाव में पार्टी का नेतृत्व मैं ही करूंगा - नवीन पटनायक

भुवनेश्वर, 25 जून। बीजू जनता दल (बीजद) के अध्यक्ष और ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि वर्ष 2029 के आम चुनाव में पार्टी का नेतृत्व वही

- पटनायक की घोषणा ने पार्टी में असमन्जस की स्थिति समाप्त की।

करेंगे। उनके इस बयान के साथ ही, पूर्व आईएएस अधिकारी सुजाता कार्तिकेयन को पार्टी के भविष्य के चेहरे के रूप में पेश किए जाने संबंधी अटकलों पर विराम लगा गया है। बीजद मुख्यालय शंख भवन में पूर्व आईएएस अधिकारी सुजाता कार्तिकेयन को पार्टी की सदस्यता दिलाने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए नवीन पटनायक ने अपनी मंशा (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

# खैरथल-तिजारा जिले के मंडी व्यापारी ने अलवर आकर सुसाइड किया

## सुसाइड से पहले व्यापारी ने फेसबुक पर पोस्ट कर लिखा कि 'आईजी और एसपी साहब एएसआई महेंद्र सिंह यादव तिजारा के खिलाफ कार्रवाई करें, ऐसे इंसान को डिसमिस करें'

अलवर, (निसं)। खैरथल-तिजारा जिले के एक मंडी व्यापारी ने अलवर आकर सुसाइड कर लिया। मरने से पहले उसने फेसबुक पर पोस्ट कर लिखा कि 'आईजी और एसपी साहब एएसआई महेंद्र सिंह यादव तिजारा के खिलाफ कार्रवाई करें। ऐसे इंसान को डिसमिस करें। मेरी सारी गवाही और सबूत मिटा दिए गए, जबकि सीओ शिवराज सिंह ने जांच कर मेरे ऊपर सोनु की तरफ से लगे एससी-एसटी के झूठे मुकदमे लगाए एफआर लगाई। महेंद्र एएसआई तिजारा ने बहुत गलत किया है। मेरे से 18 हजार रुपये रिश्वत ली। मरने वाला झूठ नहीं बोलता। सोनु से सांठगाँठ हो गई और फाइल से सारी गवाही हटा दी गई।'

फेसबुक पर पोस्ट करने के बाद व्यापारी ने तिजारा सीओ शिवराज सिंह को भी मैसेज किया, जिसके बाद उसने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया। इस दौरान सीओ शिवराज सिंह को शक हुआ

तो व्यापारी राजेश गुप्ता (52) की लोकेशन निकलवाने की कोशिश की गई। शुरूआत में लोकेशन नहीं मिली, जिसके बाद सीओ खुद जाबते के साथ उसके घर पहुंचे। वहां राजेश का बेटा मिला, लेकिन उसे भी अपने पिता के बारे में जानकारी नहीं थी कि वह कहाँ गए हैं। हालांकि राजेश पिछले तीन दिनों से गायब था। इसके बाद पुलिस ने फिर लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश की तो उसकी लोकेशन अलवर शहर की तेज मंडी के पास दिखाई दी। तिजारा पुलिस ने अलवर पुलिस को सूचना देकर मौके पर भेजा, जहां दार रॉयल गेस्ट हाउस में राजेश गुप्ता पंखे से लटका मिला। इसके बाद उसे नीचे उतारकर जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

तिजारा सीओ शिवराज सिंह ने बताया कि राजेश करीब दो साल पहले एक महिला के साथ लिंव-इन रिश्तेनाशप में रह रहा था। साथ रहने



व्यापारी का फाइल फोटो

के बाद दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। इसके बाद महिला सोनु ने राजेश पर एससी-एसटी एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया था और राजेश ने महिला के खिलाफ 420 का मामला दर्ज कराया था। दोनों मामलों में पुलिस ने

■ फेसबुक पर पोस्ट करने के बाद व्यापारी ने तिजारा सीओ शिवराज सिंह को भी मैसेज किया, जिसके बाद उन्होंने अपना फोन बंद कर लिया

■ तिजारा पुलिस ने अलवर पुलिस को सूचना देकर मौके पर भेजा, जहां एक गेस्ट हाउस में व्यापारी राजेश गुप्ता पंखे से लटका मिला

जांच करते हुए एफआर लगा दी थी। इसी के साथ राजेश को कुछ व्यवसायिक नुकसान भी हो रहा था। साथ ही राजेश ने तिजारा मंडी में किसी कच्ची पची का भी जिक्र किया था, जिसमें उसने गड़बड़ी होने की बात कही थी। शिवराज सिंह ने बताया कि राजेश ने दोपहर करीब 12 बजे उनके मोबाइल पर ये मैसेज भेजे थे, जिसके बाद पुलिस हस्तगत में आ गई और उसकी तलाश शुरू कर दी गई ताकि वह कोई गलत कदम न उठा ले, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका।

फेसबुक पोस्ट में राजेश गुप्ता ने महिला सोनु पर भी गंभीर आरोप लगाए उसने लिखा कि महिला ने उससे 5 लाख रुपये लिए थे और धमकी दी थी कि वह उसके भतीजे की शादी बिगाड़ देगी। राजेश ने अपनी पोस्ट में आरोप लगाया कि इस पूरे मामले में महिला की बहन भी शामिल है और दोनों मिलकर लोगों के साथ ठगी करती है। इसके अलावा राजेश ने फेसबुक पर महिला के साथ हुई चैट के स्क्रीनशॉट भी पोस्ट किए, जिनमें महिला की ओर से भेजे गए मैसेज दिखाई दे रहे हैं।

## कविता को ग्रामीण सेवा शिविर में मकान का पट्टा मिला

### मकान का पट्टा मिलने पर महिला का मुख्यमंत्री का आभार जताया



व्यावर की नरबदखेड़ा ग्राम पंचायत में लगे सेवा शिविर में महिला कविता को मकान का आबादी भूमि का पट्टा दिया।

जयपुर, ब्यावर। ब्यावर जिले की नरबदखेड़ा ग्राम पंचायत में लगे ग्रामीण सेवा शिविर में जब ग्राम नरबदखेड़ा निवासी कविता पत्नी प्रवीण सिंह को उसके मकान का आबादी भूमि पट्टा दिया गया, खुशी से उसके आंसू निकल आए। कविता ने बताया कि काफी समय से पट्टा नहीं मिलने के कारण उसे कई दिक्कतें आ रही थी। वह बैंक से लोन लेकर एक अतिरिक्त कमरा बनवाना चाहती थी लेकिन पट्टे के बिना बैंक लोन नहीं दे रहा था, मकान के स्वामित्व को लेकर भी मन में डर था।

ग्रामीण सेवा शिविर में कविता ने ग्राम पंचायत के माध्यम से आवेदन किया, तत्काल उसकी पात्रता की जांच की गई और शिविर में ही उसे मकान का पट्टा प्रदान कर दिया गया। कविता ने कहा कि रोटी, कपड़ा और मकान न्यूनतम जरूरत माने जाते हैं लेकिन रोटी तो आज मिल गई तो कल की रोटी

■ महिला के पास पट्टा नहीं होने से बैंक लोन नहीं दे रहा था

के लिए नया संघर्ष करना पड़ता है, कपड़े के लिए भी साल-2 साल में नये सिर से मशकत करनी पड़ती है। मकान गरीब का वह सपना होता है, एक बार पूरा हो जायें तो पूरी जिन्दगी बिना टेशन के निकल जाती है। मकान बनाकर उस सपने को देख तो लिया था, पट्टा मिलने से अब वास्तविकता में बदला है। अब मेरे बच्चों को मेरे रहने और मेरे बाद भी छत के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, उनको इस पर अधिकार का कागज मिल गया है। इसके लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार, जिन्होंने मुझे पट्टा दिलवाने के लिए कैम्प लगवाया जिस पट्टे के लिए बरसों से भटक रहे थे, आज गांव में ही मिल गया।

## अलवर में वन राज्य मंत्री ने कोचिंग सैंटरों को सील करने की कार्रवाई पर रोक लगाई

अलवर, (निसं)। अलवर में बुधवार को नयाबक के आसपास 14 कोचिंग सैंटर और लाइब्रेरी सील किए जाने के अगले ही दिन वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने इस कार्रवाई को रोकवा दिया है। गुरुवार को कोचिंग संचालकों का एक प्रतिनिधिमंडल सिकंदर हाउस में जनसुनवाई के दौरान वन मंत्री संजय शर्मा से मिला और अपनी समस्याओं से अवगत कराया।

इस मामले में कोचिंग संचालक को थपड़ मारने के आरोप में एक महिला होमगार्ड को हटा दिया गया है। वहीं, कोचिंग संचालकों ने नगर निगम के एक्सइस धर्मेश मीणा पर भी अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए

■ मंत्री ने 15 दिन का समय दिया, इस अवधि में वे फायर एनओसी प्राप्त कर लें और आग बुझाने के पुख्ता इंतेजाम पूरे करें

शिकायत सौंपी है। वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि लखनऊ में हुए अतिरिक्त के बाद सरकार के आदेश पर पूरे प्रदेश में कोचिंग सैंटर और लाइब्रेरी की जांच की गई थी। जहां आग बुझाने के उपकरण और फायर एनओसी नहीं मिली, उन्हें सील किया गया था। अलवर में भी एक

दिन यह कार्रवाई की गई, लेकिन कोचिंग सैंटर संचालकों से मुलाकात के बाद अब यह तय किया गया है कि उन्हें 15 दिन का समय दिया जाए। इस अवधि में वे फायर एनओसी प्राप्त कर लें और आग बुझाने के पुख्ता इंतेजाम पूरे कर लें। इसके लिए कोचिंग सैंटर संचालकों से एक शपथ पत्र (एफिडेविट) भी लिया जाएगा कि यदि 15 दिनों के भीतर आग बुझाने के उपकरण नहीं लगाए गए, तो आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल सीलिंग की कार्रवाई रोक दी गई है। इसके अलावा, करियर मेकर कोचिंग सैंटर के संचालक को थपड़ मारने के आरोप में दोषी महिला होमगार्ड को हटा दिया गया है।

इसके अलावा, सिकंदर हाउस में वन राज्य मंत्री के पास ट्रांसफर के आवेदन लेकर पहुंचने वाले लोगों की भी लंबी कतार लगी रही। वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि सरकार ने करीब डेढ़ साल बाद तबादलों से रोक हटाई है। यही कारण है कि इस समय तबादलों के लिए सबसे अधिक आवेदन आ रहे हैं। जितनी भीड़ गुरुवार को सिकंदर हाउस में दिखी, उससे कहीं अधिक भीड़ बुधवार को जयपुर सचिवालय में थी। हम सभी के आवेदन स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन सरकार की मंशा है कि किसी को भी अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए जहाँ पर रिक्त (खाली) है, केवल वहीं तबादले किए जाएं।

## फर्टीलाइजर सेल्स एप्लीकेशन सिस्टम का राजसमंद में शुभारंभ

### पायलट प्रोजेक्ट के रूप में राजसमंद और सिरोही जिलों को चयनित किया गया है



कृषि विभाग के आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने कृषि विज्ञान केंद्र राजसमंद में एफ का शुभारंभ किया।

जयपुर। कृषि विभाग के आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने गुरुवार को कृषि विज्ञान केंद्र राजसमंद में आयोजित कार्यक्रम में फर्टीलाइजर सेल्स एप्लीकेशन सिस्टम (एफएसएस) का शुभारंभ किया। इस अभिनव व्यवस्था को फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के रूप में राजसमंद एवं सिरोही जिलों में लागू किया गया है। कार्यक्रम में एडीएम नरेश बुनकर सहित कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, किसान एवं कृषि आदान विक्रेता उपस्थित रहे।

कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को पारदर्शी, सुगम एवं तकनीक आधारित सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि एफएसएस प्रणाली के माध्यम से किसानों को उनकी फार्मर आईडी के आधार पर अनुदानित उर्वरकों का

■ एफ के माध्यम से अनुदानित उर्वरकों का वितरण होगा, किसानों को कतारों में नहीं लगाना पड़ेगा

वितरण किया जाएगा। इससे उर्वरक वितरण व्यवस्था अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनेगी तथा वास्तविक किसानों तक समय पर खाद की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। इस प्रणाली की शुरूआत पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर राजसमंद जिले से की गई है। अब किसान अपने मोबाइल फोन के माध्यम से उर्वरक की बुकिंग कर सकेंगे तथा निर्धारित प्रक्रिया के तहत उन्हें खाद की आपूर्ति पारदर्शी तरीके से सुनिश्चित कराई जाएगी। इससे किसानों को खाद लेने के लिए लंबी कतारों में खड़ा नहीं

होना पड़ेगा तथा समय और श्रम दोनों की बचत होगी। साथ ही उर्वरकों की कालाबाजारी एवं अनियमित वितरण पर भी प्रभावी रोक लग सकेगी।

एडीएम नरेश बुनकर ने कहा कि तकनीक आधारित यह पहल किसानों को सुविधाजनक सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे उर्वरक वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी और किसानों को समय पर आवश्यक कृषि आदान उपलब्ध हो सकेगा। उन्होंने किसानों से इस प्रणाली का अधिकतम लाभ उठाने का आह्वान किया। अतिरिक्त निर्देशक कृषि खंड भीलवाड़ा श्री निरंजन सिंह राठौड़ ने कहा कि फर्टीलाइजर सेल्स एप्लीकेशन सिस्टम (एफएसएस) उर्वरक वितरण व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित एवं पारदर्शी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

## राजगढ़ में दो कारों की टक्कर में दो युवकों की मौत, एक घायल

सादलपुर, (निसं)। जयपुर से भादरा जा रही वरना कार को गलत दिशा से आ रही तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर गाड़ी ने टक्कर मार दी। हादसे में दो युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर घायल है। राजगढ़ थानाधिकारी राजेश कुमार सिहाग ने घटना का मौका निरीक्षण किया है तथा मामला दर्ज कर मृतक युवकों के शव परिजनों को सौंप दिये।

जानकारी के अनुसार हादसा 25 जून रात करीब 1.15 बजे राजगढ़ से करीब 11 किमी दूर चुरू की तरफ मुंदीताल बस अड्डा पर हुआ। पुलिस को दी रिपोर्ट में नरेश कुमार सिंह, निवासी सादरा गाड़ी और पुनित सिंह, निवासी सिकरोडी भादरा ने मामला दर्ज करवाकर बताया कि उनके भाई रामचंद्र पुत्र गोविंदराम, सिंधि निवासी वार्ड-4 भादरा और पवन

सिंह पुत्र सुरेश सिंह, निवासी सिकरोडी भादरा वरना कार से जयपुर से भादरा लौट रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रही बिना नंबर की फॉर्च्यूनर गाड़ी गलत दिशा में लापरवाही से चल रही थी। फॉर्च्यूनर गाड़ी के चालक ने वरना कार को सीधे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वरना कार में सवार रामचंद्र व पवन सिंह की मौके पर मौत हो गई।

## युवक ने जहरीली दवा खाई, मौत

डूंगरपुर, (निसं)। सदर थाना क्षेत्र के पीपलादा गांव में एक युवक ने जहरीली दवा खाकर अपनी जीवन समाप्त कर ली। युवक लंबे समय से मानसिक बीमारी से जूझ रहा था। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करार कर परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार बीती रात मानसिक तनाव के चलते माधव सिंह ने घर पर ही कोई अज्ञात जहरीली दवा खा ली। दवा का असर होते ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। परिजन उसे बेहोशी की हालत में डूंगरपुर के जनरल अस्पताल ले गए। अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद माधव सिंह को मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया।

## सड़क हादसे में युवक की मौत

मसूदा, (निसं)। मसूदा थाना क्षेत्र में देवास चौराहे के निकट सड़क दुर्घटना में एक मोटरसाइकिल सवार युवक की मौत हो गई। दुर्घटना उस समय हुई जब युवक अपने ननिहाल कानपुरा जा रहा था। पुलिस के अनुसार मृतक के भाई सुखदेव ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका भाई लक्ष्मण सिंह मोटरसाइकिल से कानपुरा जा रहा था। देवास चौराहे से पहले ब्यावर-विजयनगर मार्ग पर एक कार चालक तेज गति से वाहन चलाते हुए आया तथा मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी।

## जोधपुर में एमडी ड्रग सहित दो गिरफ्तार

### जांच में सामने आया कि एमडी मतोड़ा के पल्ली गांव से लाई गई थी

जोधपुर, (कासं)। शहर की उदयमंदिर पुलिस ने मोहनपुरा पुल के नीचे बुधवार की शाम को एक लॉडिंग टैक्सी के बॉक्स में रखी 136 ग्राम एमडी ड्रग बरामद की है। इसे लाने वाला भी टैक्सी चालक के साथ था। दोनों इसे आसपास कहीं पर सप्लाई करने वाले थे।

प्राप्त जानकारी के अनुसार आरंभिक पड़ताल में सामने आया कि यह एमडी मतोड़ा के पल्ली गांव से लाई गई है। अब देने वाले की पुलिस तलाश में जुटी है। पकड़े गए लॉडिंग टैक्सी चालक और दूसरे के युवक के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में प्रकरण दर्ज किया गया है।

थानाधिकारी सीताराम खोजा ने बताया कि मुखबिरी सूचना मिली कि मोहनपुरा पुल के नीचे सुगुरने वाली एक लॉडिंग टैक्सी में अवैध मादक पदार्थ रखा हुआ है। जांच संभवतः एमडी ड्रग हो सकती है। इस पर पुलिस

की टीम ने मोहनपुरा पुल के नीचे कपड़ों की गांठों से भरी लॉडिंग टैक्सी को रूकवाया।

उसमें सवार दोनों युवकों से पूछताछ किए जाने के साथ गाड़ी के ड्राइवर सीट के पास बॉक्स को चैक किया गया तो उसमें 136 ग्राम एमडी ड्रग मिली। इस पर चालक अजासर चाखू निवासी सुनील की गिरफ्तार किया गया। उसके साथ वाले ने अपना नाम पता एकलखोरी ओसियां निवासी खमराम होना बताया।

थानाधिकारी सीताराम खोजा ने बताया कि पूछताछ में पता लगा कि खमराम यह एमडी ड्रग लेकर आया था और कहीं सप्लाई करने वाले थे, जगह का फिलहाल खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस पूछताछ में आरोपी खमराम ने बताया कि वह यह एमडी ड्रग मतोड़ा के पल्ली निवासी सुनील से लेकर आया है। अब पुलिस सुनील की तलाश में लगी है।

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिला खण्ड सांगोद (जिला कोटा)	
निविदा सूचना संख्या 02/2026-27	दिनांक: 15.06.2026
क्रमांक: 814	
राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से सड़क / भवन कर्मा के लिये अयुक्त श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान में पंजीकृत संवेदकों एवं राज्य सरकार / केन्द्र सरकार के अधिकृत संयोजकों/केन्द्रीय/राज्यीय लोक निर्माण विभाग/डाक छाप दूर संचार विभाग / रेलवे इत्यादि में पंजीकृत संवेदकों, जो कि राजस्थान सरकार के ए. ए. बी. सी. श्रेणी के संवेदकों के समकक्ष हो, से कराई हुई ई-टेंडरिंग के माध्यम से निर्धारित प्रश्न में प्राप्त की जायेगी।	
निविदा से सम्बन्धित विवरण वेबसाइट: <a href="http://dipr.raajasthan.gov.in/tenders.asp">http://dipr.raajasthan.gov.in/tenders.asp</a> व <a href="http://www.pwd.raajasthan.gov.in">http://www.pwd.raajasthan.gov.in</a> व <a href="http://eproc.raajasthan.gov.in">http://eproc.raajasthan.gov.in</a> एवं <a href="http://sppp.raaj.nic.in">http://sppp.raaj.nic.in</a> पर देखा जा सकता है।	
(UBN NO.PWD2627WSOB05206)	(UBN NO.PWD2627WSOB05207)
(UBN NO.PWD2627WSOB05208)	(UBN NO.PWD2627WSOB05209)
(UBN NO.PWD2627WSOB05210)	(UBN NO.PWD2627WSOB05211)
(UBN NO.PWD2627WSOB05212)	(UBN NO.PWD2627WSOB05213)
(UBN NO.PWD2627WSOB05214)	(UBN NO.PWD2627WSOB05215)
(UBN NO.PWD2627WSOB05216)	(UBN NO.PWD2627WSOB05217)
(UBN NO.PWD2627WSOB05218)	(UBN NO.PWD2627WSOB05219)
(UBN NO.PWD2627WSOB05220)	(UBN NO.PWD2627WSOB05221)
(UBN NO.PWD2627WSOB05222)	(UBN NO.PWD2627WSOB05223)
(UBN NO.PWD2627WSOB05224)	(UBN NO.PWD2627WSOB05225)
(रिश्ता कुमार धाकड़) अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. जिला खण्ड सांगोद	
DIPRC/11027/2026	

### कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड सांचौर

निविदा सूचना संख्या: 03 वर्ष 2026-27	
क्रमांक: 03 / सांचौर / 2026-27/429	दिनांक: 19.06.2026
निविदा सूचना संख्या: 03 वर्ष 2026-27	
NIB No. PWD2627A1278	
राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से सौदी कार्य के आधार पर अयुक्त श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान में पंजीकृत संवेदकों एवं राज्य सरकार / केन्द्र सरकार के अधिकृत संयोजकों / केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग / डाक छाप दूर संचार विभाग / रेलवे इत्यादि में पंजीकृत संवेदकों, जो कि राजस्थान सरकार के अयुक्त श्रेणी के संवेदकों के समकक्ष हो, से निर्धारित प्रश्न में कार्य निष्पत्ती प्राप्त हो, 132.50 लाख के हिस्से ई-टेंडरिंग प्रक्रिया हेतु ऑनलाइन निविदाओं आमंत्रित की जाती है।	
ऑनलाइन निविदा आवेदन हाजलौड 24 जून 2026, 9-30 बजे से 06 जुलाई 2026, एवं अपलोड करने की तारीख 06-08-2026 बजे तक	
निविदा से सम्बन्धित विवरण वेब साइट <a href="http://dipr.raajasthan.gov.in">http://dipr.raajasthan.gov.in</a> व <a href="http://sppp.raajasthan.gov.in">http://sppp.raajasthan.gov.in</a> व <a href="http://eproc.raajasthan.gov.in">http://eproc.raajasthan.gov.in</a> पर देखा जा सकता है। सम्पूर्ण निविदा प्रक्रिया <a href="http://eproc.raajasthan.gov.in">http://eproc.raajasthan.gov.in</a> पर ऑनलाइन सम्पादित की जायेगी। इच्छुक संवेदकों को अपने डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से वेबसाइट पर <a href="http://eproc.raajasthan.gov.in">http://eproc.raajasthan.gov.in</a> पर रजिस्टर्ड कवना आवश्यक है। कार्यवार यू.बी.एन संख्या निम्नानुसार है।	
PWD2627WSOB05413, PWD2627WSOB05415	PWD2627WSOB05416, PWD2627WSOB05417
(प्रदीप पंवार) अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड सांचौर	
DIPRC/11154/2026	

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सा. नि. विभाग, विद्युत खण्ड-द्वितीय, जयपुर	
क्रमांक: 498	दिनांक: 18.06.2026
निविदा सूचना संख्या: 11/2026-27	
राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से कार्य	
(1) Rate contract for electrical work in residential buildings Model Town, Malviya Nagar, Jawahar Nagar, Vidhyadhar Nagar, Quarters/Bunglows at Jaipur	
(2) Rate contract for electrical work in residential buildings Hospital Road, Heera Bagh, Bhagat Singh Marg, Gangwal Park, C.S. Residence, DGP Residence and other Type Quarters/Bunglows Under Jurisdiction of Electrical Sub Division IV, Jaipur	
(3) Rate contract for electrical work in residential buildings Ind type, M type, N type and other Type Quarters/Bunglows at Gandhi Nagar, Jaipur	
(4) Rate contract for electrical work in residential buildings IIIRD type, IV type, Old MREC, Mully Storey and other Type Quarters/Bunglows at Gandhi Nagar, Jaipur	
(5) Rate contract for electrical work in residential buildings Vth type, VIth type, H Type, G Type, Bajaj Nagar Apartment and other Type Quarters/Bunglows at Gandhi Nagar, Jaipur	
(6) Rate contract for electrical work in residential buildings AVS Flats, E type, F type and other Type Quarters/ Bunglows at Gandhi Nagar, Jaipur	
(7) Rate contract for electrical work in residential buildings J type, J-II, JA, JB and other Type Quarters/Bunglows at Gandhi Nagar, Jaipur	
(8) SITC of CCTV Camera System for Security purpose at S-Block Mahveer Nagar Tonk road Malviya Nagar Jaipur	
(9) SITC of CCTV Camera System for Security purpose at Love Kush Nagar Tonk Road Malviya Nagar Word 145 Jaipur	
हेतु अयुक्त विद्युत श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान में पंजीकृत संवेदकों से निर्धारित प्रश्न में ई-टेंडरिंग प्रक्रिया में ऑन लाईन निविदा मध्य वेब निवारण एवं उच्च वेब (डिफेंड लाईविलिटी प्रोटीक) शर्त सहित विद्युत कार्य हेतु आमंत्रित की जाती है। सम्पूर्ण निविदा प्रक्रिया <a href="https://eproc.raajasthan.gov.in">https://eproc.raajasthan.gov.in</a> पर ऑन लाईन सम्पादित की जायेगी। निविदा से सम्बन्धित समस्त विवरण वेब साइट <a href="http://dipr.raajasthan.gov.in/tenders.asp">http://dipr.raajasthan.gov.in/tenders.asp</a> तथा <a href="http://eproc.raajasthan.gov.in">http://eproc.raajasthan.gov.in</a> तथा <a href="http://sppp.raaj.nic.in">http://sppp.raaj.nic.in</a> पर देखा जा सकता है। इच्छुक संवेदकों को ई-निविदा में भाग लेने हेतु वेब साइट <a href="http://eproc.raajasthan.gov.in">http://eproc.raajasthan.gov.in</a> पर रजिस्टर्ड कवना आवश्यक है। शुद्धि-पत्र केवल <a href="http://eproc.raajasthan.gov.in">http://eproc.raajasthan.gov.in</a> वेब साइट पर अपलोड किए जायेंगे।	
UBN NO.: PWD2627WSOB05385, PWD2627WSOB05386, PWD2627WSOB05387, PWD2627WSOB05388, PWD2627WSOB05389, PWD2627WSOB05390, PWD2627WSOB05391, PWD2627WSOB05392, PWD2627WSOB05393	
(अरविन्द खत्री) अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. विद्युत खण्ड-द्वितीय, जयपुर मो. नं. 9829456575	
DIPRC/11155/2026	

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड सुल्तानपुर	
क्रमांक: 655	दिनांक: 16/06/2026
निविदा सूचना संख्या 12/2026-27	
राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से भवन एवं सड़क निर्माण कार्य के लिये अयुक्त श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान में पंजीकृत संवेदकों एवं राज्य सरकार / केन्द्र सरकार के अधिकृत संयोजकों / केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग / डाक छाप दूर संचार विभाग / रेलवे इत्यादि में पंजीकृत संवेदकों, जो कि राजस्थान सरकार के ए. ए. बी. सी. श्रेणी के संवेदकों के समकक्ष हो, से कराई हुई ई-टेंडरिंग के माध्यम से निर्धारित प्रश्न में प्राप्त की जायेगी। निविदा से सम्बन्धित विवरण वेब साइट <a href="http://www.dipronline.org">http://www.dipronline.org</a> , <a href="http://www.pwd.raajasthan.gov.in">http://www.pwd.raajasthan.gov.in</a> व <a href="http://eproc.raajasthan.gov.in">http://eproc.raajasthan.gov.in</a> पर देखा जा सकता है। निविदा अपलोड करने की तारीख 06.07.2026 को 08-00 बजे तक।	
UBN No. - 1. PWD2627WSOB05189	2. PWD2627WSOB05190
अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड सुल्तानपुर	
DIPRC/11061/2026	

Office of the Executive Engineer, Watershed Development & Soil Conservation Bikaner			
S.N.: 177-76 Date: 18/06/2026			
NOTICE INVITING BID			
NIB No WSC2627A0466			
On the behalf of Governor of Rajasthan, bids for the execution of Construction of NRM Works under PMKSY 2.0 Projects of estimated value INR 132.58 Lakh as mentioned below are invited from interested bidders up to 30-06-2026, 06.00 PM. Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal ( <a href="https://eproc.raajasthan.gov.in">https://eproc.raajasthan.gov.in</a> or <a href="https://sppp.raajasthan.gov.in">https://sppp.raajasthan.gov.in</a> ) of the state, and <a href="http://www.watershed.raajasthan.gov.in">www.watershed.raajasthan.gov.in</a> departmental website.			
Bid No.	Block	Estimated Cost, (Rs. in lakhs)	UBN No.
1	Bikaner	132.58	WSC2627WSOB00729
[Mahesh Kumar Ajarwal] Executive Engineer WDSO, Bikaner			
DIPRC/11179/2026			

Office of the Executive Engineer, Watershed Development & Soil Conservation Bikaner			
S.N.: 177-83 Date: 18-06-2026			
NOTICE INVITING BID			
NIB No WSC2627A0473			
On the behalf of Governor of Rajasthan, bids for the execution of Construction of NRM & PRODUCTION Works under PMKSY 2.0 Projects of estimated value INR 109.22 Lakh as mentioned below are invited from interested bidders up to 30-06-2026, 08.00 PM. Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal ( <a href="https://eproc.raajasthan.gov.in">https://eproc.raajasthan.gov.in</a> or <a href="https://sppp.raajasthan.gov.in">https://sppp.raajasthan.gov.in</a> ) of the state, and <a href="http://www.watershed.raajasthan.gov.in">www.watershed.raajasthan.gov.in</a> departmental website.			
Bid No.	Block	Estimated Cost, (Rs. in lakhs)	UBN No.
1	Bikaner	44.11	WSC2627WSOB00750
1	Bikaner	65.11	WSC2627WSOB00751
[Mahesh Kumar Ajarwal] Executive Engineer WDSO, Bikaner			
DIPRC/11178/2026			

कार्यालय प्रमुख जनगणना अधिकारी एवं जिला कलक्टर, जालोर	
क्रमांक: लेखा/निविदा/2026/1248	दिनांक: 15

## कांग्रेस का डीएनए आज भी नहीं बदला : अग्रवाल

अजमेर । भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान प्रभारी डॉ. राधामोहन दास अग्रवाल ने 1975 में लगाए गए आपातकाल को लोकतंत्र के इतिहास का काला अध्याय बताते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान कांग्रेस ने देश की जनता के मौलिक अधिकार छीन लिए थे और लोकतांत्रिक संस्थाओं का गला घोट दिया था। भाजपा आज उसी दिन को 'काला दिवस' के रूप में मना रही है। गुवर्गार को अजमेर पहुंचे राधामोहन दास अग्रवाल ने आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले लोगों को याद किया। कार्यक्रम के बाद उन्होंने निकाय प्रमुखों के साथ बैठक कर संगठनात्मक विषयों पर भी चर्चा की। मीडिया से बातचीत में अग्रवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अजमेर और मुगल बाहरी शासक थे, लेकिन कांग्रेस ने अपने ही देश के लोगों के अधिकारों का हनन किया। उन्होंने कहा कि अजमेर गोरे थे और कांग्रेस ने उसी मानसिकता के साथ काम करते हुए 'काले अजमेर' की भूमिका निभाई। राज्य मंत्रिमंडल के संभावित विस्तार को लेकर पूछे गए सवाल पर भाजपा प्रभारी ने कहा कि इस विषय पर मुख्यमंत्री ही बेहतर जवाब दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि संसदन और सरकार के बीच होने वाली चर्चाएं आंतरिक विषय हैं।

# ऑनलाइन नई शिक्षा नीति जागरूकता कार्यक्रम शुरू

## भारतीय ज्ञान परंपरा और विज्ञान-प्रौद्योगिकी पर विशेषज्ञों ने साझा किए विचार

अजमेर । आर्यभट्ट इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, अजमेर द्वारा मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के सहयोग से आयोजित आठ दिवसीय ऑनलाइन नई शिक्षा नीति अभिमुखीकरण एवं जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम 30 जून 2026 तक आयोजित किया जाएगा। विज्ञान परंपरा प्रौद्योगिकी में भारतीय ज्ञान परंपरा विषय पर आधारित इस कार्यक्रम में देशभर के विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से 250 से अधिक शिक्षकों ने सहभागिता की। प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम का संचालन कार्यक्रम समन्वयक डॉ. इंद्रप्रति छाबड़ा तथा सह-समन्वयक उदय चोहान कर रहे हैं। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. सुरेश कुमार अग्रवाल और मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र के निदेशक प्रो. शिव प्रसाद ने प्रतिभागियों को संबोधित किया। उन्होंने नई शिक्षा नीति के उद्देश्यों, भारतीय ज्ञान परंपरा की प्रासंगिकता तथा उच्च शिक्षा में इसके महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यक्रम में प्रो. बी.पी. शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। प्रथम तकनीकी सत्र में प्रो. बी.पी. शर्मा ने 'प्राचीन भारत में विज्ञान एवं

## भारतीय ज्ञान परंपरा और विज्ञान-प्रौद्योगिकी पर विशेषज्ञों ने साझा किए विचार

प्रौद्योगिकी' विषय पर व्याख्यान दिया। उन्होंने आधुनिक प्रबंधन और तकनीकी दृष्टिकोण के साथ प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा को जोड़ते हुए विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से विषय को समझाया। उन्होंने भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियों, नवाचार परंपरा तथा ज्ञान प्रणाली को आधुनिक संदर्भों में प्रस्तुत किया, जिससे प्रतिभागियों को विषय की गहराई समझने का अवसर मिला। द्वितीय तकनीकी सत्र में आरएनबी ग्लोबल यूनिवर्सिटी,

## नवनि्युक्त प्रदेश उपाध्यक्ष भंवर सिंह राठौड़ का अभिनंदन

अजमेर (कांस)। संभागीय संस्कृत शिक्षाधिकारी कार्यालय, अजमेर में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ (विद्यालय शाखा) के नवनि्युक्त प्रदेश उपाध्यक्ष भंवर सिंह राठौड़ के सम्मान में भव्य अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में अधिकारियों, शिक्षकों तथा मंचालयिक कर्मचारियों ने उनका गर्वजोशी से स्वागत करते हुए सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं दीं। समारोह के दौरान संभागीय संस्कृत शिक्षाधिकारी प्रेमराज वर्मा ने माल्यापण एवं साफा पहनाकर भंवर सिंह राठौड़ का स्वागत किया। उपस्थित जनसमूह ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका अभिनंदन किया। जिला संसदन मंत्री सत्यनारायण शर्मा ने संसदन की कार्यप्रणाली, उद्देश्यों तथा आगामी शैक्षिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों की जानकारी दी। अपने संबोधन में भंवर सिंह राठौड़ ने केंद्रीय एवं प्रांतीय स्तर का आभार व्यक्त किया। हुए कहा कि वे संस्कृत शिक्षा विभाग की गरिमा को बढ़ाने तथा शिक्षक एवं कर्मचारी वर्ग की समस्याओं के समाधान के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करेंगे।

# निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर 28 को

अजमेर । यूनिवर्सल ब्रदरहुड माह के अंतर्गत लॉज फ्रेंडशिप नम्बर 47, अजमेर की ओर से रविवार 28 जून 2026 को नि:शुल्क दंत एवं स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर प्रातः 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक मानसरोवर कॉलोनी स्थित 1 बजे तक मानसरोवर कॉलोनी स्थित डॉ. विक्रम डेंटल केयर में आयोजित होगा। वर्षोपलब्ध मास्टर्ड गजेन्द्र पंचोली और सचिव जय के. करणा ने बताया कि शिविर में डॉ. विक्रम डाव्री, डॉ. आशीष, डॉ. श्रुति तथा सामान्य चिकित्सक डॉ. सुधोष अग्नीवादी देगो। शिविर में दंतों की जांच, डिजिटल दंत एक्स-रे, दंतों की सफाई, कैंबिटी, पायरिया, रूट कैंनाल, कुत्रिम दांत, दंत प्रत्यारोप संबंधी परामर्श तथा उपचार संबंधी जानकारी निशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही रक्तचाप और रक्त शर्करा की जांच भी नि:शुल्क की जाएगी। आयोजकों ने बताया कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड माह के अंतर्गत आयोजित सभी सेवा प्रकल्प वरिष्ठ सदस्य के, गौर और आनंद शर्मा के मार्गदर्शन में संचालित किए जा रहे हैं। महावीर इंटरनेशनल रीज-3 के उपाध्यक्ष (प्रचार-प्रसार) कमल गंगवाल ने इस पहल की सराहना की।

## अग्निवीरों का भव्य स्वागत

मसूदा । ग्राम पंचायत शेरगढ़ के निवासी देवराज अग्निवीर के छह माह का प्रशिक्षण पूरा कर घर लौटने पर टांगीनों में भव्य स्वागत किया। समाजसेवी अजीत सिंह ने उन्हें घुंघुमाला एवं आकर्षक फोटो प्रसेंट भेंट कर सम्मानित किया। स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी साझा की। कार्यक्रम प्रेस, सम्मान और सेवा भावना का उदाहरण बनकर सामने आया। उपस्थित लोगों ने इस पहल की सराहना करते हुए अग्निवीरों के योगदान को प्रशंसापूर्वक बताया। मसूदा उपखंड क्षेत्र में प्रशिक्षण पूर्ण कर लौटे अग्निवीरों का विभिन्न स्थानों पर साफा पहनाकर और माल्यापण कर स्वागत किया गया। इस अवसर पर देशभक्ति गीतों के साथ रैली निकाली गई।

**NAME CHANGE**

I SHAHIDA BANU is Wife of Army No. 2702581A Rank-HAV. Name- ABDUL RAJJAK Serving in Indian Army That I have changed my Name in my Husband Army service record from SHAHIDA BANU to SHAHIDA BANU Vide Affidavit No. CH 906156 Before Court Nasirabad

**दिनांक : 23.06.2026**

**आम सूचना**

सूचित हो कि मेरे पक्षकार अजीत सिंह यादव पुत्र स्व० भाग्यराज, निवासी 716-ए, तीसरी गली, विद्यार्थी, अजमेर के स्थायित्व की सम्पत्ति एम्प्लॉयी नं. 1289/10 नम्बर पर 38/3 पुना, स्थिति लार्ड-अजमेर में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 1071 वर्गमीटर है, मेरे पक्षकार ने सम्पत्ति पर एक स.बी.आई. मासपत्र अजमेर से त्रुण लेखा है। मेरे पक्षकार की उक्त सम्पत्ति पर किसी व्यक्ति द्वारा किसी प्रकार का अतिक्रमण, अनाधिकृत कब्जा या कोई बाधा अडचन उत्पन्न करता है तो मेरे पक्षकार को उसके विरुद्ध सख्त पुलिस धान, न्यायलय में कानूनी कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार होगा।

अधिकृतता अनिल कुमार, एडवोकेट  
मो. 9460895089

## कार्यालय ग्राम पंचायत काशीर पंचायत समिति अराई, जिला-अजमेर(राज.)

क्रमांक: शा.प.का./2026-27/52 दिनांक: 25.06.2026  
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत काशीर में नियम 157 (i),(ii),158, 167 के तहत निम्न आवेदन आवामीय पट्टा जारी करने के लिए प्राप्त हुए हैं। ग्राम पंचायत की बैठक निर्णयानुसार पट्टा प्रक्रिया के दौरान राज. पंचायत राज नियम 146 के अन्तर्गत आपत्ति आमंत्रित की जाती है यदि किसी भी व्यक्ति/संस्था/राजस्व विभाग/गैर सरकारी संस्था को आपत्ति हो तो आपत्ति मसूदा प्रस्ताव लेकर ग्राम पंचायत काशीर कार्यालय में 07(सात) दिवस के भीतर उपस्थित होकर प्रस्तुत करें अन्यथा बाद मियाद किसी भी प्रकार की आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा एवं आवेदनकर्ता को पट्टे जारी कर दिये जायेंगे। अतः सभी सूचित रहे।

क्र.सं.	आवेदक का नाम/पति/पिता	जाति	ग्राम	आस-पड़ोस का विवरण
1	श्री प्रधान/देवकरण जाट	जाट	खरवड़	मिसलानुसार
2	श्री रामराज/देवकरण जाट	जाट	खरवड़	मिसलानुसार
3	श्री हनुमान जाट/नारायण जाट	जाट	खरवड़	मिसलानुसार
4	श्री दिनेश चौधरी/नारायण चौधरी	जाट	खरवड़	मिसलानुसार
5	श्री रामसिंह चौधरी/गोपाल लाल चौधरी	जाट	खरवड़	मिसलानुसार
6	श्री शिवदान,राजू लाल चौधरी/हगामी लाल	जाट	खरवड़	मिसलानुसार
7	श्री शिवदान,राजू लाल चौधरी/हगामी लाल	जाट	खरवड़	मिसलानुसार
8	श्री रतना जाट/छमाजा जाट	जाट	खरवड़	मिसलानुसार
9	श्री बबलू सिंह/फ़ोज़े सिंह	राजपूत	खरवड़	मिसलानुसार
10	श्रीमती भवर कंवर/भंवर सिंह	राजपूत	खरवड़	मिसलानुसार
11	श्रीमती सीमा कंवर/राजेश सिंह	राजपूत	खरवड़	मिसलानुसार
12	श्री राजेन्द्र सिंह/शक्ति सिंह	राजपूत	खरवड़	मिसलानुसार
13	श्री धनराज चौधरी/नन्दाराम चौधरी	जाट	बंधली	मिसलानुसार
14	श्रीमती हेमा/गणेश	गुर्जर	बंधली	मिसलानुसार
15	श्रीमती समोदरा/रामकुमार	जाट	बंधली	मिसलानुसार
16	श्री छोट/रामदेव	जाट	बंधली	मिसलानुसार
17	श्री प्रधान/नन्दा	जाट	बंधली	मिसलानुसार
18	श्रीमती संतरा/सत्यनारायण	जाट	बंधली	मिसलानुसार
19	श्री जयान मल जाट/नन्दाराम जाट	जाट	बंधली	मिसलानुसार
20	श्रीमती गोपाली/शिवजीराम	जाट	बंधली	मिसलानुसार
21	श्री जसराज चौधरी/जगदीश जाट	जाट	बंधली	मिसलानुसार
22	श्री बसराज/पंचू	जाट	बंधली	मिसलानुसार
23	श्री गोपाल नाथ/हजारनाथ	जोगी	बंधली	मिसलानुसार
24	श्री शिवधर चौधरी/रामधन चौधरी	जाट	बंधली	मिसलानुसार
25	श्री हरिराम जाट/भंवरलाल जाट	जाट	श्रीरामपुरा	मिसलानुसार
26	श्री प्रधान लाल जाट/दशरथ जाट	जाट	श्रीरामपुरा	मिसलानुसार
27	श्री रामदेव/हरचन्द	जाट	श्रीरामपुरा	मिसलानुसार
28	श्री जगदीश प्रसाद चौधरी/द्वाराम चौधरी	जाट	श्रीरामपुरा	मिसलानुसार
29	श्री रामचरण जाट,प्रधान जाट/सुनगा जाट	जाट	श्रीरामपुरा	मिसलानुसार
30	श्री रामचरण जाट,प्रधान जाट/सुनगा जाट	जाट	श्रीरामपुरा	मिसलानुसार
31	श्रीमती सुधार/हरकरण	जाट	श्रीरामपुरा	मिसलानुसार
32	श्रीमती सुधार/हरकरण	जाट	श्रीरामपुरा	मिसलानुसार
33	श्री सांवरलाल/हगामीलाल	बैराव	श्रीरामपुरा	मिसलानुसार
34	श्री रतन/जस्ता	श्रीरामपुरा	श्रीरामपुरा	मिसलानुसार
35	श्री भागचन्द जाट/किशन जाट	जाट	श्रीरामपुरा	मिसलानुसार
36	श्री रामेश्वर/गोरधन	जाट	श्रीरामपुरा	मिसलानुसार
37	श्रीमती प्रेम देवी/रामेश्वर	जाट	श्रीरामपुरा	मिसलानुसार
38	श्री वकील/गोपाल	बैराव	श्रीरामपुरा	मिसलानुसार
39	श्री हनुमान जोगी/रतननाथ	जोगी	बंधली	मिसलानुसार
40	श्री हनुमान/रामदेव	बलाई	बंधली	मिसलानुसार
41	श्री ओमप्रकाश/सुवालाल	कुम्हार	खरवड़	मिसलानुसार
42	श्री सत्यनारायण/रामदेव	जाट	खरवड़	मिसलानुसार
43	श्री रामेश्वर /उममा बलाई	बलाई	काशीर	मिसलानुसार
44	श्री रामकुमार/केलाशचन्द	जाट	काशीर	मिसलानुसार
45	श्री जगदीश/रामनाथ	जाट	काशीर	मिसलानुसार
46	श्री पुरानाथ/गोदूनाथ	जोगी	काशीर	मिसलानुसार
47	श्री नाथूलाल जाट/बलदेव जाट	जाट	काशीर	मिसलानुसार
48	श्री कालू राम जाट/सुनगा जाट	जाट	काशीर	मिसलानुसार
49	श्रीमतीसंतोष/गणेश बैराव	बैराव	काशीर	मिसलानुसार
50	श्रीमती प्रेम देवी/नारायण	बैराव	काशीर	मिसलानुसार
51	श्री श्रवण लाल जाट/छिन्नमल जाट	जाट	काशीर	मिसलानुसार
52	श्री रामसिंह चौधरी/छिन्नमल जाट	जाट	काशीर	मिसलानुसार
53	श्री शशीराम/नाथ जाट	जाट	खरवड़	मिसलानुसार

नोट- उपरोक्त सूचीनुसार यदि पूर्व में किसी स्तर से कोई पट्टा जारी हो किसी प्रकार का आपसी भाई बंटवार और विवाद हो या किसी न्यायालय में कोई प्रकरण विचारधीन हो या किसी भी पड़ोसी व्यक्ति,संस्था, सरकारी विभाग को उपरोक्त सूची के आवेदनकर्ताओं के संबंध में किसी भी प्रकार की आपत्ति हो तो आपत्ति होने की तारीख से 07 दिवस के भीतर ग्राम पंचायत कार्यालय में आपत्ति मसूदा प्रस्तावित प्रस्तुत करें। बाद मियाद किसी भी कार्यवाही के लिए ग्राम पंचायत जिम्मेदार नहीं रहेगी और न ही किसी आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। यदि पूर्व में पट्टे पर पट्टा जारी होने पाया जाता है तो पूर्व में जारी पट्टा स्तर : ही निरस्त समझा जायेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी पट्टाधारी की होगी एवं पट्टाधारक कानूनी कार्यवाही के लिए जिम्मेदार होगा एवं समस्त जिम्मेदारी आवेदनकर्ता की होगी। अतः सूचित रहे।

क्र.सं.	आवेदक का नाम/पति/पिता	जाति	ग्राम	आस-पड़ोस का विवरण
40	श्री हनुमान/रामदेव	बलाई	बंधली	मिसलानुसार
41	श्री ओमप्रकाश/सुवालाल	कुम्हार	खरवड़	मिसलानुसार
42	श्री सत्यनारायण/रामदेव	जाट	खरवड़	मिसलानुसार
43	श्री रामेश्वर /उममा बलाई	बलाई	काशीर	मिसलानुसार
44	श्री रामकुमार/केलाशचन्द	जाट	काशीर	मिसलानुसार
45	श्री जगदीश/रामनाथ	जाट	काशीर	मिसलानुसार
46	श्री पुरानाथ/गोदूनाथ	जोगी	काशीर	मिसलानुसार
47	श्री नाथूलाल जाट/बलदेव जाट	जाट	काशीर	मिसलानुसार
48	श्री कालू राम जाट/सुनगा जाट	जाट	काशीर	मिसलानुसार
49	श्रीमतीसंतोष/गणेश बैराव	बैराव	काशीर	मिसलानुसार
50	श्रीमती प्रेम देवी/नारायण	बैराव	काशीर	मिसलानुसार
51	श्री श्रवण लाल जाट/छिन्नमल जाट	जाट	काशीर	मिसलानुसार
52	श्री रामसिंह चौधरी/छिन्नमल जाट	जाट	काशीर	मिसलानुसार
53	श्री शशीराम/नाथ जाट	जाट	खरवड़	मिसलानुसार

प्रशासक ग्राम पंचायत काशीर, पं.स.अराई, जिला अजमेर

## आम सूचना

मेरे पिता गोपाल उर्फ गोपालराज शर्मा पुत्र प्रसादलाल जाटि शाहण निवासी ग्राम दयिता की मृत्यु दिनांक 1.1.1989 को मेरे पिता स्वयं ग्राम दयिता के हो गई थी, जिसका पूर्व में इन्द्राज पंचायत दयिता में नहीं करवाया था। अतः मेरे पिता गोपाल उर्फ गोपालराज शर्मा का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अराई तहसील कार्यालय में आवेदन किया है। मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने बाद फिर किसी व्यक्ति को आपत्ति हो तो 7 दिन में मय दस्तावेज स्वयं उपस्थित होकर अपनी आपत्ति तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। बाद मियाद कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।

अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर लोक सूचना  
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री विराम गोपाल पुत्र दिनेश कुमार गोपाल की ग्राम लोहागल के खसरा नम्बर 1000 भूखण्ड संख्या 79 में क्षेत्रफल 22.22 वर्गज अर्थात् 185.80 वर्ग मीटर के भूखण्ड की संपत्तिका विवरण हेतु प्रक्रियाधीन है। उक्त नियमन के सम्बन्ध में दैनिक समाचार पत्र में विज्ञापित जारी कर 7 दिवस की आपत्ति आमंत्रित की जाती है। अतः किसी भी हितदायक को इस नियमन के सम्बन्ध में आपत्ति हो तो आम सूचना के 7 दिवस के भीतर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा नियमन कार्यवाही कर दी जायेगी।  
उपायुक्त (उत्तर) अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर लोक सूचना  
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती नवल कंवर पति रणजीत सिंह की ग्राम लोहागल (देव नगर अजमेर) के खसरा नं 1116 भूखण्ड संख्या 194 में क्षेत्रफल 116.66 वर्गज के भूखण्ड की पत्रवली विवरण हेतु प्रक्रियाधीन है उक्त नियमन के सम्बन्ध में दैनिक समाचार पत्र में विज्ञापित जारी कर 7 दिवस की आपत्ति आमंत्रित की जाती है अतः किसी भी हितदायक को इस नियमन के सम्बन्ध में आपत्ति हो तो आम सूचना के 7 दिवस के भीतर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा नियमन कार्यवाही कर दी जायेगी।  
उपायुक्त उत्तर अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर

अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर लोक सूचना  
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती नवल कंवर पति रणजीत सिंह की ग्राम लोहागल (देव नगर अजमेर) के खसरा नं 1116 भूखण्ड संख्या 194 में क्षेत्रफल 116.66 वर्गज के भूखण्ड की पत्रवली विवरण हेतु प्रक्रियाधीन है उक्त नियमन के सम्बन्ध में दैनिक समाचार पत्र में विज्ञापित जारी कर 7 दिवस की आपत्ति आमंत्रित की जाती है अतः किसी भी हितदायक को इस नियमन के सम्बन्ध में आपत्ति हो तो आम सूचना के 7 दिवस के भीतर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा नियमन कार्यवाही कर दी जायेगी।  
उपायुक्त उत्तर अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर

विवादकों के स्थिरीकरण के लिए समन  
(अदालत 5 के नियम 1 और 5 दीर्घी प्रक्रिया संहिता, 1908)  
न्यायालय श्रीमान् उपायुक्त अधिकारी कुमानसिंह जी  
वाद पत्र क्रमांक- 51/2026  
कमल कुमार बनारस बलद्वीरसिंह वर्मा, कंवर पत्नी रसुवीर सिंह जाति जाट राजपूत, कामनारा पुत्र नन्दाराम जाति कुमावत मनी निवासी आसपुरा तहसील कुमानसिंह सिटी जिला डीडरनगर-कुमानसिंह (राज.)  
वादी ने आपके विरुद्ध 53, 58, व 188 R.T.A.का एक वाद इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है जो इस न्यायालय में पंजीकृत कर लिया गया है और इस वाद में किये गए दावे का उत्तर देने के लिये आवाही इस न्यायालय द्वारा दिनांक 28/07/2026 की पेशी निवृत्त की गई है। आप न्यायालय में या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा उपस्थित हो सकते हैं जिनसे सख्त अनुदेश दिए गये हैं और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सत्यता प्रश्नों का उत्तर दे सकें या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिक्रिया का लिखित सन्ध दायित्व करें और उत्तर देने से सब दस्तावेज जो आपके कब्जे में या शक्ति में हैं देश करें जिन पर आपकी प्रतिक्रिया या दायित्व/पुनर्वाह का दावा या प्रतिक्रिया आधारित है। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर यह दावे आपके कब्जे व शक्ति में हैं उनका प्रतिक्रिया या पुनर्वाह करने या प्रतिवादी के सम्बन्ध में साक्ष्य के रूप में निरूप करते हैं तो आप पेशी दस्तावेजों को उचितकरित सन्ध के बाद उपायुक्त को अपने वाली सूची में प्रेषित करें।  
आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उत्तर दावती गयी तारीख पेशी पर न्यायालय में उप-न्याय नहीं होयेगी तो आपके सूचनापत्र व उक्तानुपिटा आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा वह नोटिस मेरे हस्ताक्षर/मेरे निदेशानुसार न न्यायालय की मुहर से आज दिनांक 23/06/2026 को जारी किया गया।  
-अद्वैतराम शर्मा-रीडर उपायुक्त अधिकारी, कुमानसिंह सिटी (डीडरनगर-कुमानसिंह)

कार्यालय नगर परिषद किशनगढ़ (अजमेर) राजस्थान  
क्रमांक- न.प.कि/कृषि भूमि नियम/2026/613 दिनांक: 25.06.2026  
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर परिषद किशनगढ़ में खसरा ग्राम मदनगढ़ के खसरा 89 का भूखण्ड संख्या 04 का कुल क्षेत्रफल 183.00 वर्गज (आवामीय प्रक्रियामें) हेतु पट्टा चार्ज हेतु कृषि भूमि नियम के तहत आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त आवेदन भूखण्ड नियम में संशोधित किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो इस सूचना के प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में इस कार्यालय को लिखित में आवेदिता/पत्र साक्ष्य / विवरण सहित कार्यालय सन्ध में दर्ज करवाए।

क्र.सं.	आवेदक का नाम	भूखण्ड का विवरण	खसरा ग्राम का नाम एवं खसरा नं. व क्षेत्रफल	प्रस्तावित कृषि भूमि नियम
77	1. वन कुमार जैन पुत्र केशव कुमार पुत्र केशवराज	चन्दन देवी फली तेजवरन	कडवावा कॉलोनी खसरा पत्रा विवरणमन्.ख.सं. 71 से 78, 88, 89 90 नि.स. भू.सं. 55 व 56 का उत्तरी हिस्सा	183.33 आवामीय SQ.Yard

कार्यालय नगर पालिका विजयनगर जिला ब्यावर राजस्थान  
क्रमांक- न.प.कि/निर्माण रवी/2024/1520 दिनांक: 24.6.2026  
सर्वसाधारण को सूचना प्रेषित किया जाता है कि निर्माकित भूकान निर्माण हेतु निम्न भूखण्ड निर्माण प्रस्तावित प्राप्त हुई है, अगर किसी को आपत्ति/उत्तर हो तो विज्ञापित प्रकाशन के 7 दिवस में मय सख्त के अर्थात्स्थावरकर्ता के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं, बाद मियाद, मुजरने कोई उत्तर / आपत्ति मान्य नहीं होगी।

क्र.सं.	आवेदक का नाम	भूखण्ड का विवरण	खसरा ग्राम का नाम एवं खसरा नं. व क्षेत्रफल	प्रस्तावित कृषि भूमि नियम
50	शिवु निर फली जितेन्द्र कुमार जैन	महावीर कॉलोनी (मार्गसिंह का) वरत द्वितीय ख.सं. 1086/1 भू.सं. 85		125.40 आवामीय SQ.MTR

कार्यालय नगर परिषद किशनगढ़ (अजमेर) राजस्थान  
क्रमांक- न.प.कि/कृषि भूमि नियम/2026/731 दिनांक: 24.06.2026  
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर परिषद किशनगढ़ में खसरा ग्राम मदनगढ़ के खसरा 89 का भूखण्ड संख्या 04 का कुल क्षेत्रफल 183.00 वर्गज (आवामीय प्रक्रियामें) हेतु पट्टा चार्ज हेतु कृषि भूमि नियम के तहत आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त आवेदन भूखण्ड नियम में संशोधित किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो इस सूचना के प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में इस कार्यालय को लिखित में आवेदिता/पत्र साक्ष्य / विवरण सहित कार्यालय सन्ध में दर्ज करवाए।

क्र.सं.	आवेदक का नाम	भूखण्ड का विवरण	खसरा ग्राम का नाम एवं खसरा नं. व क्षेत्रफल	प्रस्तावित कृषि भूमि नियम
1.	श्री रजनी कुमारी पत्नी श्री गोविंद चौधरी निवासी रजनी कृष्ण नगर, मदनगढ़ किशनगढ़ जिला अजमेर		खसरा ग्राम का नाम एवं खसरा नं. व क्षेत्रफल 183.00 वर्गज	प्रस्तावित कृषि भूमि नियम (आवामीय प्रक्रियामें) पट्टा चार्ज हेतु

कार्यालय नगर परिषद किशनगढ़ (अजमेर) राजस्थान  
क्रमांक- न.प.कि/कृषि भूमि नियम/2026/721 दिनांक: 22.06.2026  
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर परिषद किशनगढ़ में खसरा ग्राम मदनगढ़ के खसरा 725 का भूखण्ड संख्या ... का कुल क्षेत्रफल 200.00 वर्गज (आवामीय प्रक्रियामें) हेतु पट्टा चार्ज हेतु कृषि भूमि नियम के तहत आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त आवेदन भूखण्ड नियम में संशोधित किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो इस सूचना के प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में इस कार्यालय को लिखित में आवेदिता/पत्र साक्ष्य / विवरण सहित कार्यालय सन्ध में दर्ज करवाए।

क्र.सं.	आवेदक का नाम	भूखण्ड का विवरण	खसरा ग्राम का नाम एवं खसरा नं. व क्षेत्रफल	प्रस्तावित कृषि भूमि नियम
1.	श्री रजनी कुमारी पत्नी श्री गोविंद चौधरी निवासी रजनी कृष्ण नगर, मदनगढ़ किशनगढ़ जिला अजमेर		खसरा ग्राम का नाम एवं खसरा नं. व क्षेत्रफल 200.00 वर्गज	प्रस्तावित कृषि भूमि नियम (आवामीय प्रक्रियामें) पट्टा चार्ज हेतु

कार्यालय





# आपातकाल ने संविधान और देश की आत्मा को कुचला- भजनलाल

## मुख्यमंत्री ने संविधान हत्या दिवस पर लोकतंत्र सैनानियों की पेंशन 5 हजार रूपए बढ़ाकर 25 हजार रूपए की

जयपुर, 25 जून। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि 25 जून 1975 को कांग्रेस सरकार द्वारा लगाए गए आपातकाल ने संविधान और लोकतंत्र की आत्मा को कुचलने का काम किया। संविधान की रक्षा में लोकतंत्र सैनानियों का अविस्मरणीय योगदान है। उन्होंने कहा कि इतिहास के उन घटनाक्रमों को याद रखना बेहद जरूरी है, जब देश के लोकतांत्रिक ढांचे और नागरिकों के मौलिक अधिकारों को न केवल नुकसान

■ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने स्वार्थ की खातिर आपातकाल लगाया और संविधान की हत्या की।

■ समारोह को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, सांसद घनश्याम तिवारी और कार्यक्रम संयोजक अशोक परनामी ने भी संबोधित किया।

पहुंचाया गया, बल्कि देश को जेलखाना तक बना दिया गया था।

मुख्यमंत्री गुरुवार को राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान ऑडिटोरियम, दुर्गापुरा में "संविधान हत्या दिवस" के अवसर पर आयोजित लोकतंत्र सैनानी सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र और संविधान



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान ऑडिटोरियम, दुर्गापुरा में "संविधान हत्या दिवस" के अवसर पर आयोजित लोकतंत्र सैनानी सम्मान समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों का सम्मान किया गया।

की भावना की रक्षा करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।

मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र सैनानियों की मासिक पेंशन को 5 हजार रुपये बढ़ाकर 25 हजार रुपये तथा मासिक चिकित्सा सहायता को 1 हजार रुपये बढ़ाकर 5 हजार रुपये करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने लगभग 1 लाख से अधिक नेताओं, स्वयंसेवकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और पत्रकारों को बिना मुकदमे चलाए जेल में कैद कर दिया था। इस दौरान,

नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सीमित करने के साथ ही, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और मीडिया पर सेंसरशिप जैसे कड़े प्रतिबंध लगाए गए थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने स्वार्थ की खातिर आपातकाल लगाया और संविधान की हत्या की। आज कांग्रेस पार्टी संविधान को दुहाई देती है और संविधान को बचाने का पाखंड करती है।

राज्यसभा सांसद एवं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि आपातकाल भारतीय लोकतंत्र पर

सबसे बड़ा हमला था।

राज्यसभा सांसद एवं लोकतंत्र सैनानी घनश्याम तिवारी ने कहा कि आपातकाल की प्रभुभूमि गुजरात के नवनिर्माण आंदोलन और बिहार के छात्र-युवा आंदोलन से तैयार हुई थी, जिसका नेतृत्व लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने किया।

पूर्व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष एवं कार्यक्रम संयोजक अशोक परनामी ने कहा कि 25 जून 1975 की आधी रात को देश पर थोपा गया आपातकाल हमारे लोकतांत्रिक इतिहास पर काला धब्बा है।

## भाजपा में भारी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) ऐसा लगता है कि सत्तारूढ़ दल के भीतर बड़ा मंथन चल रहा है।

ये घटनाक्रम जहां सरकार और भाजपा के भीतर बढ़ती थकान के संकेत दे रहे हैं, साथ ही सरकार और संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी की ओर भी इशारा करते हैं। केन्द्रीय मंत्रिपरिषद में नए चेहरों को शामिल किए जाने की चर्चाओं के बीच यह भी कहा जा रहा है कि भाजपा नेतृत्व मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सहित, कई राज्यों में नेतृत्व परिवर्तन की संभावना पर विचार कर रहा है।

तो फिर मोहन यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच क्या संबंध हैं? अखिलेश यादव इस बारे में कहते हैं, "भाजपा योगी आदित्यनाथ को निशाना बनाने के लिए मोहन यादव को बदनाम करने की साजिश रच रही है। यदि मोहन

यादव पर आरोप है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी 300-600 एकड़ जमीन हासिल की है। ये आरोप इसलिए लगाए जा रहे हैं, क्योंकि भाजपा कुछ मुख्यमंत्रियों को बदलने का रास्ता तलाश रही है।"

उल्लेखनीय है कि भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी ने आज उत्तर प्रदेश भाजपा इकाई का पुनर्गठन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दूसरे पुत्र नीरज को उत्तर प्रदेश भाजपा का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि गृह मंत्री अमित शाह के सहयोगी अंकुर शर्मा को राज्य भाजपा का सचिव बनाया गया है। देवीविजन पत्रकार यशवंत सिंह को भी राज्य इकाई के नए सचिवों में स्थान मिला है। कुल मिलाकर 19 उपाध्यक्ष, 8 महासचिव और 19 सचिव नियुक्त किए गए हैं। राज्य के सभी छह क्षेत्रों के प्रमुखों को भी बदल दिया गया है।

## विवादित वीडियो में मेरी शक्ल का मास्क पहने बहुरूपिया है- भगवंत मान

चंडीगढ़, 25 जून। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विवादित वीडियो के संबंध में दावा किया है कि एक साजिश के तहत किसी व्यक्ति को

■ मुख्यमंत्री मान ने डिजिटल सबूत पेश करते हुए वीडियो अकाल तख्त साहिब जांच के लिये भेजने की बात कही

मास्क पहनाकर यह वीडियो शूट किया गया है।

इस साजिश में कनाडा निवासी जगमन समरा की भूमिका अहम है। गुरुवार को पंजाब के मोहाली में भगवंत

मान ने इस संबंध में डिजिटल सबूत पेश करते हुए दावा किया कि यह वीडियो भी अकाल तख्त साहिब को जांच के लिए भेजा जाएगा।

## 'पासपोर्ट ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) से धारक की पहचान एक भारतीय के रूप में दर्ज होती है। पुरस्कार विजेता गीतकार जावेद अख्तर ने मंत्रालय के इस रुख को "बेतुका" बताया। उन्होंने सवाल किया कि यदि सरकार को यह विश्वास ही नहीं है कि पासपोर्ट धारक वास्तव में भारतीय नागरिक है, तो फिर पासपोर्ट जारी करने के पीछे सरकार का तर्क या आधार क्या है?

## वैक्सिन, एंटीबायोटिक व कैंसर की दवाओं पर क्यूआर कोड लगेगा

नई दिल्ली, 25 जून। देश में नकली और घटिया दवाओं पर लगाम लगाने के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाया है। मंत्रालय ने ड्रग्स नियम, 1945 में संशोधन करते हुए, वैक्सिन, एंटीमाइक्रोबियल (एंटीबायोटिक), नारकोटिक एवं साइकोट्रॉपिक तथा कैंसर रोधी दवाओं को क्यूआर कोड आधारित ट्रैक एंड ट्रेस प्रणाली के दायरे में शामिल कर दिया है।

नए नियमों के तहत, इन दवाओं के निर्माताओं को उत्पाद की पैकेजिंग पर बारकोड या क्यूआर कोड लगाना अनिवार्य होगा। यदि प्राथमिक पैकेजिंग पर पर्याप्त जगह नहीं है तो क्यूआर कोड द्वितीयक पैकेजिंग पर लगाया जा सकेगा। क्यूआर कोड स्कैन करने पर दवा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे यूनिफ़ाइड कोड ऑफ़ इंटेंशन और ब्रांड नाम, निर्माता का नाम और पता, बैच नंबर, निर्माण एवं एक्सपायरी तिथि, मैनुफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर और आवश्यक होने पर एक्सपिरेट्स की जानकारी उपलब्ध होगी।

## एसआईटी की रिपोर्ट पर राम मंदिर चंदा चोरी प्रकरण में एफआईआर दर्ज

### एफआईआर में नामजद सभी आठ व्यक्ति गिरफ्तार, व्यापक स्तर पर गिरफ्तारियों की संभावना

■ आप पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने राम मंदिर को मिले चंदे में हुई अनियमितताओं के बारे में दस्तावेज गुरुवार को एसआईटी को सौंपे।

लखनऊ, 25 जून। राम मंदिर चंदा चोरी केस में एफआईटी की सिफारिश के बाद रामजन्मभूमि कोतवाली में एफआईआर दर्ज हुई। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में अब सबसे बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। जानकारी के मुताबिक, श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। अब तक इस मामले में एसआईटी जांच चल रही थी, लेकिन एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच का दायरा और गंभीर हो गया है।

सूत्रों के अनुसार, सीसीटीवी में चोरी करते दिखे लोग और उनकी मदद करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। यूपी सरकार के निर्देश पर बीएनएस के तहत 306, 316(5), 317(4), 317(5) 61, 3(5) के

तहत एफआईआर दर्ज की गई है। 8 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें टिन्नु यादव, लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा के नाम शामिल हैं। जिन लोगों के पास से रकम मिली है, उन लोगों को एफआईआर में नामजद किया गया है। सभी आरोपों में राम शंकर यादव टिन्नु, अनुकल्प मिश्रा, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडेय, लवकुश मिश्रा, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और मनीष यादव को हिरासत में लिया गया है। कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं।

बता दें कि राम मंदिर चंदा चोरी के मामले में एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की मांग पर सरकार ने 3 सदस्यीय एसआईटी गठित की थी। अयोध्या में एसआईटी 6 दिनों तक रही। ट्रस्ट के सदस्यों से पूछताछ की। वहीं, गुरुवार को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने राम मंदिर को मिले चंदे में हुई अनियमितताओं को लेकर संबंधित दस्तावेज एसआईटी को सौंप दिए। उन्होंने कहा कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

## तीन-चार दिन में मानसून बिहार, झारखंड, यूपी तक पहुंच जायेगा

### दिल्ली- एनसीआर में 26 को तेज हवाओं के साथ बारिश होने का अनुमान

नई दिल्ली, 25 जून। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने आगामी दिनों में उत्तर-पश्चिम और पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसी बीच उत्तर-पूर्वी राज्यों सहित, बिहार तथा उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में लू का प्रकोप भी जारी रहने की संभावना है।

मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में 26 जून को आंशिक रूप से बादल छाए रहने और दोपहर-शाम के समय तेज हवाओं और गरज के साथ हल्की बारिश होने के आसार हैं। इस दिन दिल्ली में अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान क्रमशः 39-41 डिग्री सेल्सियस और 25-27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। 27 और 28 जून को भी यही स्थिति रहने का अनुमान है। उल्लेखनीय है कि राजधानी में

आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने और दोपहर-शाम के समय तेज हवाओं और गरज के साथ हल्की बारिश होने का अनुमान जताया गया था। फिलहाल, राजधानी के निवासियों ने आज के मौसम में गर्माहट महसूस की है। मौसम विभाग के मुताबिक, अगले 3-4 दिनों में दक्षिण-पश्चिम मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। मौसम अधिकारियों के पूर्वानुमान के अनुसार, पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश जारी है। इसके अलावा, पूर्वोत्तर राज्यों के साथ-साथ इस सप्ताह पश्चिमी तट, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल तथा अन्य क्षेत्रों में भी भारी बारिश (7-20 सेमी) होने की संभावना है।

## प्रधानमंत्री ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) के साथ बातचीत करेंगे। वे दोनों देशों के बीच सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री सेरेलस की राष्ट्रीय असेंबली को भी संबोधित करेंगे और वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगे। मंत्रालय का कहना है, यह यात्रा भारत और सेरेलस के बीच मजबूत और स्थायी दोस्ती को और सशक्त करेगी तथा सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को और मजबूत करेगी।

## राहुल गांधी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) राहुल गांधी द्वारा कोर्ट में अपनी गलती स्वीकार कर खेद व्यक्त करने के बाद, शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए उनके इस खेद को स्वीकार कर लिया। दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति बनने के साथ ही लंबे समय से खिंच रहा यह हाई-प्रोफाइल मानहानि मामला हमेशा के लिए समाप्त हो गया।

## अगले ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) साफ कर दी। सुजाता कार्तिकेयन के बीजद में शामिल होने के बाद राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई थी कि पूर्व नौकरशाह एवं वी.के. पांडेयन की पत्नी सुजाता को वर्ष 2029 के चुनावों के लिए पार्टी के संभावित नेतृत्व के रूप में तैयार किया जा सकता है। लेकिन नवीन पटनायक के ताजा बयान ने इन सभी अटकलों को खारिज कर दिया है।

मीडिया से बातचीत में पटनायक ने कहा, मैं मीडिया और सभी लोगों की जानकारी के लिए एक बार फिर दोहराना चाहता हूँ कि अगले चुनाव में बीजू जनता दल का नेतृत्व मैं ही करूंगा। मैं इसे पूरी तरह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ।

## कई वर्षों बाद ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) के कुछ वर्षों द्वारा बहुत बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है, जबकि वास्तव में यह एक सामान्य घटना है। गलत लंबे समय से गांधी परिवार से मुलाकात का समय पाने की कोशिश कर रहे हैं। वे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) में कोई पद पाना चाहते हैं। एआईसीसी में उनके कई शुभचिंतक, जो वरिष्ठ नेता हैं, उनके लिए लगातार प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन अब तक इसका कोई खास असर नहीं हुआ है।

दिलचस्प बात यह है कि राजस्थान के प्रभारी एआईसीसी महासचिव सुखविंदर सिंह रंधावा ने के. सी. वेणुगोपाल के साथ बैठक की। और मौतों को कम किया जा सकता है।" उन्होंने तर्क दिया कि जैसे-जैसे शहरों का विस्तार हो रहा है और इन्फ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क आपस में जुड़ रहे हैं, प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों (अलर्ट वॉरनिंग सिस्टम) में निवेश और भी महत्वपूर्ण होता जा रहा है।

उन्होंने कहा कि स्मार्टफोन का व्यापक उपयोग आपात स्थितियों के दौरान नागरिकों तक महत्वपूर्ण सुरक्षा जानकारी सीधे पहुंचाने का एक शक्तिशाली माध्यम बन चुका है। पंथरी ने यह भी कहा कि आपदा-प्रतिक्रिया क्षमता को केवल जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में नहीं देखा जाना चाहिए। समुदायों को भूकंप, बाढ़, तूफान और अत्यधिक गर्मी जैसी अनेक प्राकृतिक आपदाओं के लिए तैयार रहना चाहिए।

वेनेजुएला की यह चेतावनी आपदा प्रबंधन में हो रहे एक बड़े बदलाव की ओर भी संकेत करती है। अब केवल पारंपरिक निगरानी केन्द्रों पर निर्भर रहने के बजाय सरकारें

औपचारिक रूप से यह बैठक पंजाब के मुद्दों पर चर्चा के लिए थी, लेकिन इसके साथ ही, राजस्थान में कुछ महत्वपूर्ण बदलावों पर भी विचार किया गया। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा राजस्थान में नए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की नियुक्ति का है, जो गोविंद सिंह डोटासरा का स्थान लेंगे।

डोटासरा को न केवल रंधावा, बल्कि के. सी. वेणुगोपाल का भी समर्थन प्राप्त रहा है। राजस्थान और दिल्ली के राजनीतिक हलकों में आम राय यह है कि यदि सचिन पायलट को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनाया गया, तो राजस्थान में कांग्रेस के लिए राजनीतिक हालात काफी मुश्किल हो सकते हैं।

## युद्ध विराम पर अमल होना शुरू, इज़रायल ने दक्षिण लेबनान से सैनिक हटाये

तेल अवीव, 25 जून। इज़रायल ने दक्षिणी लेबनान के कुछ हिस्सों से सैनिक हटाने शुरू कर दिए हैं। इज़रायली न्यूज वेबसाइट आई24 ने गुरुवार को एक अमेरिकी सूत्र के हवाले से बताया कि इज़रायल ने "अच्छी नीयत" दिखाते हुए दक्षिणी लेबनान के कुछ हिस्सों से सैनिक हटाने शुरू कर दिए हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, दक्षिणी लेबनान में तथाकथित बाफ़र जोन के जिन हिस्सों से इज़रायली रक्षा बलों (आईडीएफ) ने अपने सैनिक हटाए हैं, वहाँ लेबनानी सेना का कब्ज़ा हो जाएगा। खबरों के मुताबिक, एक इज़रायली अधिकारी ने कहा कि आईडीएफ दक्षिणी लेबनान में अपनी मौजूदगी बनाए रखेंगे।

## शिक्षक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं ने भर्ती की प्रथम उतर कुंजी पर आपत्ति जताई थी, जिस पर अंतिम उतर कुंजी में 11 प्रश्न डिलीट कर दिए थे। इसके अलावा कई उतर बदल दिए गए थे। याचिकाकर्ताओं की ओर से कई अन्य प्रश्नों पर भी आपत्ति दर्ज कराई गई थी, लेकिन उन पर विचार ही नहीं किया गया। बोर्ड की पुस्तक के अनुसार याचिकाकर्ताओं के उतर सही हैं, लेकिन फिर भी चयन बोर्ड ने उन्हें सही नहीं किया। ऐसे में याचिका में हाईकोर्ट से आग्रह किया गया है कि याचिकाकर्ताओं को बोसअ अंक देकर नियुक्ति दी जाए। इसके अलावा, कोर्ट का फैसला आने तक भर्ती के तहत होने वाली नियुक्तियों पर भी रोक लगाई जाए।

## युद्ध विराम पर अमल होना शुरू, इज़रायल ने दक्षिण लेबनान से सैनिक हटाये

तेल अवीव, 25 जून। इज़रायल ने दक्षिणी लेबनान के कुछ हिस्सों से सैनिक हटाने शुरू कर दिए हैं। इज़रायली न्यूज वेबसाइट आई24 ने गुरुवार को एक अमेरिकी सूत्र के हवाले से बताया कि इज़रायल ने "अच्छी नीयत" दिखाते हुए दक्षिणी लेबनान के कुछ हिस्सों से सैनिक हटाने शुरू कर दिए हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, दक्षिणी लेबनान में तथाकथित बाफ़र जोन के जिन हिस्सों से इज़रायली रक्षा बलों (आईडीएफ) ने अपने सैनिक हटाए हैं, वहाँ लेबनानी सेना का कब्ज़ा हो जाएगा। खबरों के मुताबिक, एक इज़रायली अधिकारी ने कहा कि आईडीएफ दक्षिणी लेबनान में अपनी मौजूदगी बनाए रखेंगे।

राजस्थान सरकार

श्री नरेन्द्र मोदी  
माननीय प्रधानमंत्री

श्री भजनलाल शर्मा  
माननीय मुख्यमंत्री

## प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (PMAY-G)

आवास प्लस 2024 सर्वे के आधार पर तैयार ड्राफ्ट वरीयता सूची एवं "विकसित भारत- जी राम जी" (VB-G RAM G) योजना अंतर्गत गांव के विकास कार्यों की कार्य योजना के अनुमोदन हेतु

### विशेष ग्राम सभा

तारीख :- 29 जून, 2026 | स्थान:- ग्राम पंचायत भवन

**विनम्र अपील**

आवासहीन / कच्चा आवासधारी परिवार ग्राम सभा में भाग लेकर वरीयता सूची का अवलोकन करें तथा अपना पक्ष / आपत्ति प्रस्तुत करें

ग्राम सभा के निर्णय से असहमत होने पर जिला कलक्टर को 7 दिवस में अपील प्रस्तुत कर सकते हैं

**विकसित भारत- जी राम जी योजना अंतर्गत**

- जल सुरक्षा एवं जल संबंधी कार्य
- मूलभूत ग्रामीण अवसंरचना संबंधी कार्य
- आजीविका से जुड़े विकास कार्य
- जलवायु एवं आपदा प्रबंधन से जुड़े कार्य

के प्रस्ताव ग्राम सभा में प्रस्तुत करें।

ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में जारी <https://pmayg.dord.gov.in>